शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 252 | गुवाहाटी | रविवार, 19 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

महिला आरक्षण पर राजग और विपक्षी दलों ने एक दूसरे को घेरा पेज 2
काकोपथार में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, कड़ी सजा की मांग पेज 3
मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला, गहलोत ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल पेज 5
टी20 विश्वकप की तैयारियों में लगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

तुम किसी को दोष मत दो। अगर तुम अपने हाथ आगे बढ़ा कर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ बांधकर खड़े रहो। अपने वालों को शुभकामनाएं दो और उन्हें उनके रास्ते जाने दो.. । आप दोष देने वाले कोई नहीं होते है।

– स्वामी विवेकानंद

पीएम का देश के नाम संबोधन, महिला आरक्षण बिल पर बोले–

विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने देश की माताओं और बहनों के समक्ष अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की उड़ान को विपक्ष के द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने देश की महिलाओं से माफी भी मांगी और कहा कि हम अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज यहां देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सफल नहीं हो सके। अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं देश की माताओं और बहनों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की भी आलोचना की और उन पर विधेयक को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने विधेयक की विफलता के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा सहित विभिन्न दलों की स्वार्थी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक की विफलता को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की और उन पर जनहित से ऊपर राजनीति रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति के कारण देश की माताओं और बहनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी समूहों ने विधेयक के गिरने का जश्न मनाया और कहा कि विधेयक के गिरने पर ये वंशवादी दल तालियां बजा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक की विफलता को लेकर विपक्षी दलों पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को उनके उचित अवसर से वंचित करके विपक्षी दल एक तरह से अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है, देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं कई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वे अपने अपमान को कभी नहीं भूलतीं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया, वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। उन्होंने कहा कि नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। संसद में नारीशक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, वे लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भाप रही हैं और सच्चाई भी भलीभांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने –शेष पृष्ठ दो पर

ममता ने वोट बैंक के लिए बंगाल बेच दिया : हिमंत

कोलकाता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य के संसाधनों को *बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों* के हवाले करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें सत्ता से हटाना होगा, *वरना हम बंगाल को गंवा देंगे।* भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शर्मा ने कालिम्पोंग में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि असम और त्रिपुरा की भाजपा सरकारों ने *बांग्लादेशी मुसलमानों* को भारत में घुसने से रोका है, जबकि बंगाल में अवैध घुसपैठ जारी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल का पूरा खजाना बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए आरक्षित कर दिया है। उन्होंने वोट के लिए इस भूमि को बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दिया। शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से बनर्जी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ममता बनर्जी –शेष पृष्ठ दो पर

संसद में विधेयक पर भाजपा की हार मोदी सरकार के पतन की शुरुआत : ममता

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया है कि डिलिमिटेशन (परिसीमन) विधेयक को लेकर संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पतन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के राज्यों के साथ राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की साजिश कर रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर –शेष पृष्ठ दो पर

बिहार विस का विशेष सत्र 24 को सम्राट चौधरी साबित करेंगे बहुमत

पटना (हि.स.)। बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र आगामी 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र केवल एक दिन का होगा और सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नई सरकार को इसी दिन सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आह्वान-पत्र में सभी विधायकों से समय पर सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही –शेष पृष्ठ दो पर

सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि : शिवराज

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार के लिए *किसान हित सर्वोपरि* है और किसी भी प्रतिकूल मौसम परिस्थिति, विशेषकर अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र पूरी तरह तैयार है। शिवराज चौहान ने आज दिल्ली में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की एक उच्चस्तरीय वर्चुअली समीक्षा के दौरान यह बात कही। मंत्री ने कहा, मौसम संबंधी पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास से संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। –शेष पृष्ठ दो पर

होर्मुज में भारतीय टैंकर पर फायरिंग भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब

नई दिल्ली। होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी गनबोट्स से गोलीबारी की खबरों के बाद कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक, होर्मुज में फायरिंग के बाद दो भारतीय जहाज भी वापस लौटे हैं। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि भारत के किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर गोलीबारी की घटना को लेकर ईरानी राजदूत को तलब किया है। जहाज और उसके सभी क्रू मेंबर्स के सुरक्षित होने की खबर है, हालांकि अधिकारियों ने जहाज की पहचान का खुलासा नहीं किया। टैंकर ट्रैकर्स डॉट कॉम के मुताबिक, इस घटना के बाद कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिनमें भारत के झंडे वाले एक सुपरटैंकर भी शामिल थे। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि स्थिति को –शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में एनएच-202 पर दो की गोली मारकर हत्या

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर के उखरूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-202 पर अज्ञात हमलावरों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में एक पूर्व सेना कर्मी भी शामिल बताया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना उखरूल जिले के एक संवेदनशील क्षेत्र में उस समय हुई जब दोनों व्यक्ति वाहन से यात्रा कर रहे थे। तभी घात लगाए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों की मौके पर ही –शेष पृष्ठ दो पर

रुनीखाता हिंसा अब नियंत्रण में 15 गिरफ्तार : पुलिस

रुनीखाता। अधिकारियों के मुताबिक, भारत-भूटान सीमा से सटे असम के चिरांग जिले में भड़की हिंसा अब नियंत्रण में है। रुनीखाता पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले रिपु-चिरांग आरक्षित वन में अवैध अतिक्रमण के आरोपों के कारण अशांति फैली थी। शुक्रवार को भड़की हिंसा के सिलसिले में कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस एवं अर्धसैनिक बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चिरांग और कोकराझार जिलों में हुई हिंसा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नुमल महाट्टा ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पेड़ों की कटाई और अस्थायी बस्तियां (जिन्हें स्थानीय रूप से –शेष पृष्ठ दो पर

महिला आरक्षण पर भाजपा आक्रोशित

राहुल के आवास पहुंचीं महिला सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई हिरासत में

नई दिल्ली। संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मकसद से लाए गए विधेयक को संसद से पारित नहीं कराया जा सका। संसद में मिली इस विफलता भाजपा आक्रोशित है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए महिला सांसदों, नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।दोनों खेमों के नेताओं की बयानबाजी जारी है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन –शेष पृष्ठ दो पर

लोकप्रियता में पीएम मोदी फिर शीर्ष पर, 10वें स्थान पर ट्रंप

नई दिल्ली। वैश्विक लोकप्रियता सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी शीर्ष पर बरकरार हैं। अमेरिकी ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी हालिया सर्वेक्षण के नतीजों में यह बात सामने आई है। सर्वे में यह भी कहा गया कि वैश्विक राजनीति में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा साबित कर दिया है। करीब 24 लोकतांत्रिक देशों में किए गए इस सर्वे में शामिल 70 फीसदी लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का –शेष पृष्ठ दो पर

संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली (हि.स.)। संसद का बजट सत्र शनिवार को दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के साथ समाप्त हो गया। यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी उथल-पुथल भरा रहा और इसे विशेष बैठकों के लिए निर्धारित समय से आगे बढ़ाया गया था, जिसमें चुनावी सुधारों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दलेने और परिसीमन प्रक्रिया लागू करने से संबंधित था, लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि पारित होने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने समापन संबोधन में बताया कि सदन की कार्य-उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत रही। उन्होंने जानकारी दी कि 28 जनवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 31 बैठकें हुईं, जो 151 घंटे 42 मिनट तक चलीं। सत्र के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 पर करीब 13 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष ने बताया कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पर 21 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 131 सदस्यों ने हिस्सा लिया, हालांकि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 9 विधेयक पारित हुए। इसके अलावा –शेष पृष्ठ दो पर

मुंबई में पुलिस की हिरासत से बांग्लादेशी महिला फरार

नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला पुलिस हिरासत से फरार हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीरजान बेगम इस्माइल शेख उर्फ नसरीन को कुछ अन्य बांग्लदेशी नागरिकों के साथ कुर्ला स्थित पुलिस क्वर्टव में हिरासत में रख गया था। गुरुवार तड़के, उसने ड्यूटी पर मौजूद महिला कॉन्सटेबल से वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। कॉन्सेटबल ने उसे इजाजत दे दी। –शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

महिला आरक्षण पर राजग और विपक्षी दलों ने एक दूसरे को घेरा

नई दिल्ली (हि.स.)। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के बाद शनिवार को सत्तारूढ़ राजग और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखा प्रहार किया। एक ओर जहां सरकार और उसके सहयोगियों ने इसे देश के लिए काला दिन बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे संविधान की रक्षा का क्षण बताते हुए जश्न मनाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरलेन रिजिजू ने विधेयक के पारित न होने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इसके विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इसे कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर ऐसा कलंक बताया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। रिजिजू ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाला यह एक ऐतिहासिक विधेयक था, जिसे राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि इसे 2023 एक्ट के आधार पर लागू किया गया तो जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्विन्यास का असर कई राज्यों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दक्षिण भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ रही है और नहीं चाहती कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को न्याय दिलाने में बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण को साथ लाने का उद्देश्य सीटों की संख्या बढ़ाना और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दलेना था। केंद्रीय मंत्री एवं लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने कहा कि यह प्रस्ताव सभी राज्यों के लिए संतुलित और न्यायसंगत था, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इसमें बाधा डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका हक मिले। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस पर निराशा जताते हुए कहा कि महिलाएं हतोत्साहित हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और यह विधेयक देर-सबेर पारित होगा। वहीं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह सिर्फ परिसीमन का विरोध नहीं, बल्कि 2029 में संसद में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को रोकने की कोशिश है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण दलेने के प्रयास में विपक्ष ने बाधाएं खड़ी कीं, जिससे यह विधेयक पारित नहीं हो सका। ऐसे में महिला राजग सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार उन्हें हिस्सा दलेना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने इसमें रुकावटें डालीं और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं होने दिया। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए इसे संविधान की रक्षा बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इसे परिसीमन के साथ जोड़ा, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इसे राजनीतिक रणनीति के तहत पेश किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण को पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन परिसीमन को इससे जोड़ना गलत था। उन्होंने इसे राजनीतिक खेल करार देते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि यदि सरकार अलग से महिला आरक्षण विधेयक लाती है, तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।

हिमंत के भड़काऊ बयान को लेकर तृणमूल ने चुनाव आयोग से की शिकायत

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर *भड़काऊ, विभाजनकारी और अप्रमाणित आरोप* लगाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि उनके बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को निशाना बनाते हैं। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में तृणमूल ने कूचबिहार जिले में एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए असम के मुख्यमंत्री के कथित बयान का उल्लेख किया है। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आती है तो मांस खाने पर रोक लगने को लेकर ममता बनर्जी की चिंता दरअसल केवल बीफ को लेकर है, न कि चिकन, मटन या मछली को लेकर। तृणमूल सूत्रों के अनुसार, इस तरह का बयान न केवल अनुचित राजनीतिक टिप्पणी है, बल्कि यह धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने और राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का एक सुनियोजित प्रयास भी है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि हिमंत विश्व शर्मा ने यह दावा कर *भड़काऊ और निराधार* बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू इलाकों में बीफ की दुकानें खोल रहे हैं और तस्करी कर रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि इस तरह के बयान एक समुदाय के खिलाफ संदेह और शत्रुता का माहौल बनाने के उद्देश्य से दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में जमा कराए गए पत्र में कहा है कि इस तरह की बयानबाजी किसी एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाकर उसे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताती है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कलंकित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

अमृतसर में 450 करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलीजेंस विंग ने सीमा पार से हो रही तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए करीब 450 करोड़ रुपए कीमत की 64.62 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके दो तस्करों को काबू किया है। यह गैंग पाकिस्तानी तस्कर मूसा द्वारा चलाया जा रहा था। मूसा कुछ साल पहले भारत में उस समय चर्चा में आया था जब कस्टम ने यहां अटारी-बाघा बार्डर पर एक मालगाड़ी से 532 किलो हेरोइन बरामद की थी। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि अमृतसर में पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलीजेंस विंग के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि यह हेरोइन पाकिस्तान से मंगवाई गई है, जिसे अब आगे सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने इससे पहले की पकड़ लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार विदेश में बैठे हैंडलर्स और पाकिस्तान के मूसा गैंग से भी जुड़े हुए हैं। यह गिरोह सीमा पार से ड्रग तस्करी कर पंजाब और अन्य राज्यों में सप्लाई करने का काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सरवन सिंह गुर्जर निवासी अवा गांव और शमशेर सिंह गांव इकतियारनगर के रुप में हुई है। दोनों को गांव माहल के पास से पकड़ा गया है।

पीएम फसल बीमा योजना में राज्य ने खरीफ 2025 के लिए जारी किए 1150.04 करोड़

जयपुर (हिंस)। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सत्र के लिए पंजीकृत 2.17 करोड़ बीमाधारकों को 1150.04 करोड़ रुपए की राज्यांश अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि योग्य फसल बीमा पॉलिसीधारक किसानों को खरीफ 2025 के तहत देय लगभग 2237 करोड़ रुपए के दावों का शीघ्र, त्वरित एवं प्राथमिकता आधार पर वितरण किया जाएगा। इससे प्रभावित किसान परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जो उनकी आय सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना किसानों को असफल बुआई, बुआई से कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति तथा कटाई उपरांत 14 दिनों की अवधि में पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस पर पूर्ण बीमा लाभ प्रदान करेगी।

देश में ईंधन आपूर्ति सामान्य, भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार सतर्क

नई दिल्ली (हि.स.)। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर केंद्र सरकार ने बताया कि तेल आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बावजूद देश में तेल और गैस आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, बंदरगाहों का संचालन सामान्य है और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षित वापसी तथा सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें। एलपीजी उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बुकिंग करने और वितरकों के पास अनावश्यक भीड़ न लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही, पीएनजी, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बचत करने का आग्रह किया गया है। केंद्र ने कहा कि रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर संचालित हो रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और किसी भी वितरण केंद्र पर गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। 17 अप्रैल को 52 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। वहीं, 23 मार्च से अब तक 5 किलोग्राम के 17.25 लाख से अधिक एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, दवा, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दी गई है। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडरों की उपलब्धता दोगुनी कर दी गई है। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को संकट पूर्व स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा ऑटो एलपीजी की बिक्री में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पीएनजी विस्तार सुधारों से जुड़े अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन दिए जा रहे हैं। सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं, जिससे एलपीजी पर दबाव कम किया जा सके। आपूर्ति और मांग के संतुलन के लिए बुकिंग अंतराल को शहरी क्षेत्रों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक किया गया है। साथ ही केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के लिए सशक्त किया गया है।

पृष्ठ एक का शेष

विपक्ष ने आधी आबादी ...

संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। इस विधेयक के तहत, 2011 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 किया जाना था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करने के लिए सीटें बढ़ाई जानी थीं। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन आवश्यक संख्या जुटाने में विफल रहा। शुक्रवार रात लोकसभा में विधेयक पर हुए मतदान में 298 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।

ममता ने वोट बैंक ...

को बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा, अन्यथा एक दिन बांग्लादेशी मुसलमान हमसे यह राज्य छीन लेंगे। भाजपा नेता ने दावा किया कि बनर्जी के कार्यकाल में उत्तर बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, हम इस क्षेत्र से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में सत्ता में आने पर गोरखालैंड मुद्दे का संवैधानिक समाधान तलाशेगी और गोरखाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। शर्मा ने कूचबिहार जिले के दिनहाटा में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने उन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ *सांप्रदायिक रंग वाली, भड़काऊ और विभाजनकारी* टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की इस कार्रवाई से वह डरने वाले नहीं हैं। भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता और आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद बनाने के प्रयास का भी उल्लेख किया और कहा कि अगर असम में ऐसा कोई प्रयास हुआ होता तो वह कड़े कदम उठाते और इसमें शामिल व्यक्ति को जेल भेज देते।

संसद में विधेयक पर भाजपा ...

विफल कर दिया। हावड़ा जिले के पांचला क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद पहुंचे और विधेयक का विरोध करते हुए मतदान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता में उनकी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर केंद्र सरकार वास्तव में डिलिमिटेशन का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, ताकि राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में बदले जा सकें। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बावजूद उनसे 20 सांसद भेजने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 21 सांसद दिल्ली भेजे। उन्होंने कहा कि यह भाजपा को हराने की रणनीति का हिस्सा था और विपक्ष ने संसद में भाजपा को पराजित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में मिली हार के बाद अब भाजपा को जमीन पर भी पराजय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल हमेशा देश को रास्ता दिखाता है और इस बार भी बंगाल से भाजपा को सत्ता से हटाने की लड़ाई शुरू होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के अधिकारों और आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन देश को बांटने वाली किसी भी नीति का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा पर भ्रामक प्रचार और झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर भाजपा को कड़ा संदेश दिया जाए।

बिहार विस का विशेष...

निर्धारित समय पर शुरू होगी और सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस विशेष सत्र में नई सरकार के गठन से जुड़े कई अहम कार्य पूरे किए जाएंगे। इसमें विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव, बहुमत परीक्षण और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा सत्र होगा, जिसमें वे सदन में मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी पहली बार इस भूमिका में नजर आएंगे। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। संविधान और संसदीय परंपरा के अनुसार, जब भी नई सरकार बनती है या मुख्यमंत्री बदलता है, तो उसे सदन में फ्लोर टेस्ट (बहुमत परीक्षण) के जरिए यह साबित करना होता है कि उसके पास विधायकों का पर्याप्त समर्थन है। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास स्पष्ट बहुमत है, जिससे सम्राट चौधरी सरकार को बहुमत साबित करने में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना कम है।

होर्मुज में भारतीय टैंकर ...

लेकर भ्रम के कारण भारतीय कच्चे तेल के टैंकर वापस लौट गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से अभी तक कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला है। ईरानी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान की नौसेना ने दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर पीछे हटने के लिए कहा। इनमें से एक जहाज भारतीय झंडे वाला वीएलसीसी सुपरटैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल और लेबनान में हिजबुल्ला के बीच 10 दिन के युद्धविराम के दौरान होर्मुज कमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिससे दुनियाभर के जहाज मालिकों और ऊर्जा बाजारों को बड़ी राहत मिली। हालांकि, ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने बाद में बताया कि अगर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रही, तो यह रास्ता बंद रहेगा। फारसी खाड़ी में काम करने वाले जहाज मालिकों ने भी रेडियो सलाहों की जानकारी दी है कि जहाजों को रास्ता पार करने से पहले अनुमति ललेना जरूरी है। सरकारी समाचार एजेंसी नूर न्यूज ने शनिवार को कहा कि यह जलमार्ग सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है, लेकिन न्यूज एजेंसी ने यह पुष्टि नहीं की कि क्या जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। होर्मुज में इसी कंफ्यूजन के बीच, हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही है। आज शनिवार सुबह ग्रीक और भारतीय कच्चे तेल के टैंकरों ने अचानक यू-टर्न ले लिया। वे पहले दुबई के तट के पास के पानी से होर्मुज की ओर उत्तर-पूर्व दिशा में पूरी तरह से भरे हुए आगे बढ़ रहे थे। कई जहाज अब ईरान के केश्म द्वीप के पास खड़े हैं, ठीक उसी जगह के करीब जहां से उन्होंने अपना रास्ता बदला था। जबकि एक अन्य जहाज ने कई घंटों से अपनी जियोलोकेशन (भौगोलिक स्थिति) की जानकारी नहीं भेजी है।

मणिपुर में एनएच-202 ...

मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

रुनीखाता हिंसा अब...

पॉलीथीन-बांस शिविर के नाम से जाना जाता है) स्थापित किए जाने की खबरों के बाद अशांति शुरू हुई। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में साफ की गई जमीन, कटे हुए पेड़ और बांस व प्लास्टिक की चादरों से बनी अस्थायी संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। इसके बाद, वन विभाग ने पुलिस की सहायता से अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया। अधिकारियों ने दोहराया है कि आरक्षित वन के अंदर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण गैरकानूनी है और पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। इससे पहले, 16 अप्रैल को, कथित तौर पर वन भूमि को साफ करने के आरोप में 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप विरोध प्रदर्शन हुए और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुईं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लगभग 25 से 30 परिवार कुछ समय से वन क्षेत्र में रह रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि इनमें से कुछ परिवार नदी के कटाव या अतीत के जातीय संघर्षों के कारण अपने घर खोने के बाद वहां बस गए थे। यह वन क्षेत्र बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत आता है, जहां वन भूमि पर अतिक्रमण लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। रिपु-चिरंग आरक्षित वन पहले मानस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था और बाद में सरकार द्वारा इसे सिखना ज्वलाओ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) कुंजन बसुमतारी ने बताया कि रुनीखाता रेंज के अंतर्गत लगभग 1,714 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,000 हेक्टेयर है। वन विभाग ने पहले भी इसी तरह के अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रुनिखाटा रेंज के अंतर्गत वन विभाग के एक कार्यालय पर उपद्रवियों ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी कर्मियों की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में आ गई। वर्तमान में, वन विभाग की प्रथम बटालियन के लगभग 50 जवान क्षेत्र में तैनात हैं, जिनमें से एक लापता है। 303 राइफल भी बरामद की गई है। इसी बीच, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी ने शनिवार को घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ व्यक्तियों के कृत्यों को पूरे आदिवासी समुदाय पर दोषारोपण का आधार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रुनिखाटा वन रेंज कार्यालय द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बीटीसी को सौंपी जाएगी, जो इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी। मोहिलारी ने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने वन भूमि की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

राहुल के आवास पहुंचीं ...

के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने से आक्रोशित भाजपा नेताओं ने विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने और राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने विपक्ष के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले तीस वर्षों से देश की आधी आबादी, यानी महिलाएं लगातार अपमान सह रही हैं। उन्होंने बताया कि यह विधेयक बार-बार सदन में लाया गया, लेकिन कभी इसे फाड़ दिया गया, कभी फेंक दिया गया और कभी इसका विरोध किया गया। गुप्ता ने विपक्ष के बदलते बहानों पर सवाल उठाए, जैसे परिसीमन, पुनर्गठन या सीटों की संख्या बढ़ाना। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हितैषी होने के विपक्ष के दावों पर भी सवाल उठाया और पूछा कि तीन तलाक कानून का विरोध क्यों किया था। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु एक तटस्थ प्राधिकरण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि परिसीमन 2026 में होना तय है और कांग्रेस इसे रोक नहीं सकती। सहरावत ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विधेयक का विरोध केवल एक राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए महिलाएं केवल वोट बैंक हैं, वे सत्ता साझा करने से पीछे हट गए।

लोकप्रियता में पीएम ...

ग्राफ अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में काफी ऊंचा है। वहीं, दूसरी ओर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस मामले में पिछड़ गए हैं, उन्हें दुनिया का सबसे अलोकप्रिय नेता आंका गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग (63 फीसदी) और तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस (55 फीसदी) रहे। लेकिन मोदी शीर्ष पर रहे। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह भी कहा गया कि एक ओर जहां भारतीय प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकार्यता और मजबूत हो रही है। वहीं, यूरोप के प्रमुख देशों के नेताओं को जनता के विरोध और अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता का स्तर भी गिर गया है। लोकप्रियता के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं, जिनसे 75 प्रतिशत जनता असंतुष्ट है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची में नीचे से 10वें स्थान पर हैं। ईरान के साथ संघर्ष जैसी चुनौतियों के बावजूद, लगभग 38ल अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज का समर्थन किया है। बता दें, 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग लगभग 47-51 प्रतिशत के बीच थी। अप्रैल 2026 तक इसका स्तर -18 के पास पहुंच गया, जिससे वे आधुनिक समय के सबसे कम लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बन गए।

संसद के दोनों सदन ...

सदन में लोक महत्व के 326 मुद्दे उठाए गए और नियम 377 के तहत 650 मामले प्रस्तुत किए गए। ओम बिरला ने बताया कि सत्र में 126 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। साथ ही, संसदीय समितियों द्वारा 73 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए और कुल 2089 दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 18 भारतीय भाषाओं में 181 वक्तव्य दिए गए, जिनका सफलतापूर्वक अनुवाद किया गया। सत्र के दौरान वामपंथी उग्रवाद पर अल्पकालिक चर्चा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय भी सदन में उठाए गए। वहीं राज्य सभा का 270वां सत्र भी शनिवार को संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को सफल बताते हुए सदस्यों के योगदान की सराहना की। सभापति ने कहा कि बजट सत्र संसद के तीनों सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लिए गए निर्णय देश की विकास दिशा तय करते हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की कुल उत्पादकता 109.87 प्रतिशत रही और सदन ने 157 घंटे 40 मिनट तक कार्य किया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से हुई, जो चार दिनों तक चली और इसमें 79 सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। केंद्रीय बजट 2026-27 पर भी चार दिनों तक व्यापक चर्चा हुई, जिसमें 97 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा, दो प्रमुख मंत्रालयों के कामकाज पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सदन ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रियों के स्वत: बयान भी सुने। वहीं, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी महत्वपूर्ण रहा। सभापति ने बताया कि सत्र के दौरान 50 निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। साथ ही, 12 क्षेत्रीय भाषाओं में 94 अवसरों पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। सत्र के दौरान राज्यसभा में 117 प्रश्न उठाए गए, 446 शून्यकाल उल्लेख हुए और 207 विशेष उल्लेख किए गए। इस सत्र में हरिवंश को तीसरी बार राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया, जिस पर सदन के सभी दलों ने उन्हें बधाई दी। सभापति ने सदन के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए सभी नेताओं, सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद *वंदे मातरम्* की धुन के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

मुंबई में पुलिस की ...

जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो उनकी तलाश शुरू की कई, लेकिन महिला नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में उसे अपने पति मनीष बलदेव राजभर उर्फ इस्माइल शेख के साथ परिसर से भागते हुए देखा गया। अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस महिला और उसके पति की पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके खिलाफ हिरासत से भागने और भागने में मदद करने के आरोप में भारतीय न्याय संहित से संबंधित प्रविधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

सरकार के लिए किसान ...

वर्ष 2000-2016 के बीच अल नीनो का असर ज्यादा होता था लेकिन आज की उन्नत तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर प्रबंधन के कारण हम कृषि उत्पादन में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल संभावित जोखिम का आकलन करना नहीं बल्कि समय रहते ऐसे सभी कदम उठाना है जिससे किसानों का आत्मविश्वास बना रहे, खेती की निरंतरता प्रभावित न हो और खरीफ सत्र सुचारु रूप से आगे बढ़े। मंत्री ने भरोसा जताया कि बेहतर जल प्रबंधन, तकनीकी विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों और समय पर की गई तैयारियों के बल पर संभावित चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकेगा और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अनुसार, इस वर्ष मानसून सामान्य से कुछ कम (92 प्रतिशत) रहने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए। जैसे जल प्रबंधन: देश के जलाशयों में वर्तमान जलस्तर सामान्य से 127 प्रतिशत बेहतर है, जो खरीफ की सिंचाई के लिए राहत की बात है। बीज उपलब्धता: मुख्य और वैकल्पिक फसलों के बीजों की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक सुनिश्चित की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व भी तैयार है। आकस्मिक योजना: जिला स्तर पर ऐसी योजनाएं सक्रिय की गई हैं जो मानसून में देरी या सूखे की स्थिति में किसानों को *जलवायु-सहनशील* किस्मों और वैज्ञानिक सलाह से मदद करेंगी। समीक्षा बैठक के साथ-साथ मंत्री ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत उत्तर प्रदेश में 20 एलएमटी आलू की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद 6,500.9 रुपये प्रति मीट्रिक टन के मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को कम दाम पर फसल बेचने से मुक्ति मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 203.15 करोड़ रुपये होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत चने (बंगाल ग्राम) की खरीद सीमा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी गई है। इससे राज्य के दलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। कर्नाटक के तूर उत्पादक किसानों को राहत देते हुए एमएसपी पर खरीद की अवधि को 15 मई 2026 तक (30 दिन का विस्तार) बढ़ा दिया गया है। इससे उन किसानों को लाभ होगा जो अब तक अपनी फसल नहीं बेच पाए थे। कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि राज्यों के साथ निरंतर समन्वय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेखेला चादर पहनकर चोरी करने वाले दो पुरुष एवं एक महिला चोर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी गुवाहाटी के वशिष्ठ थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां दो पुरुष चोर पारंपरिक असमिया महिला पोशाक मेखेला चादर पहनकर रात के समय चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान गगन बर्मन और जानमणि शर्मा के रूप में हुई है। दोनों आरोपित महिलाओं के कपड़े पहनकर इलाके में घूमते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो और आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे सकें। जांच में यह भी सामने आया है कि जानमणि शर्मा की पत्नी धनदा देवी भी इन दोनों के साथ चोरी की घटनाओं में शामिल रहती थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को महिलाओं के वेश में घूमते हुए देखा गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें पहचान कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए गए दो वाहन और सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। मामले की आगे जांच जारी है।

काकोपथार में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, कड़ी सजा की मांग

तिनसुकिया (हिंस)। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिलांतर्गत काकोपथार इलाके के लाजुम गांव में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शनिवार की सुबह से भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को जाम कर दिया, जिससे हजारों गाड़ियां फंस गईं। मृतकों की पहचान काकोपाथर के निवासी एवं काकोपाथर फुटबॉल कोचिंग सेंटर में गोलकीपर के तौर पर काम करने वाले प्रणजीत दास और तेजी गांव के शशांक मोरान के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर रात बिहू उत्सव के दौरान हुई। बताया जा

रहा है कि एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के समय दोनों युवक कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर ही बैठे थे। दोनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों और स्थानीय निवासियों ने उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बोलेरो गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर एएस-01वी-0399) काकोपाथर की तरफ से आ रही थी, तभी उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुमदुमा पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे में शामिल गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। शनिवार सुबह उन्होंने काकोपाथर पुलिस स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को जाम करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए और मृतकों के परिवारों के लिए तत्काल न्याय, साथ ही उचित मुआवजा और पुनर्वास उपायों की मांग की। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हाईवे के दोनों ओर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिससे पूरे इलाके में आवाजाही ठप हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से अपील की गई है कि वे प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को दूर करने और यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। इस मामले में अभी और जानकारी का इंतजार है।

रंगिया : विप्र महापरिषद का भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी

रंगिया (विभास)। विप्र महापरिषद रंगिया के तत्वावधान में भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह एक दिवसीय कार्यक्रम आगामी 19 अप्रैल (रविवार) को स्थानीय श्रीश्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जायेगा। जिसका शुभारंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा द्वारा धर्म-ध्वजा उत्तोलन के साथ सुबह 8 बजे किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8-30 बजे मूर्ति स्थापना एवं पूजा-अर्चना राज कुमार वैद्य के नेतृत्व में संपन्न होगी। वहीं मुख्य आकर्षणों में सुबह 9-30 बजे से सुंदरकांड पाठ (मुख्य पाठक: हरीप्रसाद शर्मा), सुबह 10-30 बजे से हनुमान चालीसा पाठ (मुख्य पाठिका: श्रीमती अनीता शर्मा), दोपहर 11 बजे महाआरती एवं शोभा यात्रा, दोपहर 1-00 बजे महाप्रसाद शामिल हैं। इसके अलावा संध्या 7 बजे 108 दीप प्रज्ज्वलन, संध्या आरती एवं छप्पन भोग के बाद रात्रि 9 बजे बजरंग भजन मंडली, रंगिया द्वारा भजन-संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा, सचिव लक्ष्मण शर्मा तथा संयोजक राज कुमार वैद्य ने कार्यक्रम में समाजजनों से सपरिवार उपस्थिति की विनम्र अपील की है।

दक्षिण-पश्चिम रंगिया क्रिस्टी विकास समिति का 38वां केंद्रीय रंगाली बिहू सम्मेलन शुरू

रंगिया (विभास)। दक्षिण-पश्चिम रंगिया क्रिस्टी विकास समिति के सौजन्य से 38वां केंद्रीय रंगाली बिहू सम्मेलन 19 अप्रैल (रविवार) को मोहखली मिलन चौक में आयोजित होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजान वैश्य, महासचिव यादव चंद्र दास के साथ समिति के अध्यक्ष निपेन कलिता और सचिव पबिन डेका ने सभी ग्रामीणों से सादगीपूर्ण भागीदारी और सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम सुबह 8 बजे अजान वैश्य द्वारा समिति का ध्वज फहराने के साथ शुरू होगा। इसके बाद निपेन कलिता बिहू ध्वज फहराएंगे। सुबह 8-30 बजे ग्राम विकास समितियों के ध्वज, 8-45 बजे शहीद तर्पण गोलोक वैश्य और सेवानिवृत्त शिक्षक काशीराम डेका द्वारा और इसके पश्चात 9 बजे स्मृति तर्पण (हरेंद्र नाथ डेका, दिनमणि डेका, अरविंद वैश्य द्वारा) होगा। सुबह 9-30 बजे वृक्षारोपण (गगन चंद्र दास, सुंधिया; समिंद्र नाथ वैश्य, बरमुरा; श्रीमती गौरी कलिता, मोहखली द्वारा) के बाद 10 बजे से वेक्शन प्रतियोगिता, 10-30 बजे विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और दोपहर 2 बजे चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। शाम 6 बजे पुरस्कार वितरण (अमरज्योति वैश्य, सहायक प्रबंधक आईटी विभाग एनआईपीएलओ शिलांग और बिश्वजीत कलिता, असम पुलिस निरीक्षक द्वारा), उसके बाद 6-30 बजे दीप प्रज्ज्वलन एवं सम्मान समारोह (धर्मेश्वर दास द्वारा प्रज्ज्वलन; सांसद व भाजपा असम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया सहित गणमान्य लोगों को सम्मान) कार्यक्रम होगा।

लखीपथार में अवैध शिकारियों ने काटे जिंदा पालतू हाथी के दोनों दांत

तिनसुकिया (हिंस)। राज्यभर में रंगाली बिहू के उल्लासपूर्ण माहौल के बीच तिनसुकिया के लखीपथार वनक्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई हुई। अवैध शिकारियों ने एक जिंदा पालतू हाथी के दोनों दांत काट लिए। इस घटना को लेकर इलाके में भारी रोष व्याप्त है। घटना के संबंध में हाथी के महावत के अनुसार, मार्घेरिटा के सोनजॉय दोवानिया नामक व्यक्ति के स्वामित्व वाले मंगल सिंह नामक हाथी को चराने के लिए वन विभाग को सूचित करते हुए लखीपथार वनक्षेत्र में रखा गया था। अन्य दिनों की तरह बीते 14 अप्रैल की शाम को भी हाथी को निर्दिष्ट स्थान पर बांधकर माहवत अपने घर चला गया। अगले दिन यानी 15 अप्रैल की सुबह बांधे गये स्थान पर जब हाथी नहीं देखा गया, तो इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। महावत के अनुसार हाथी पहले कई बार अपने बंधन को छुड़ाकर आसपास के इलाकों में घूमने चला जाता था, इसी आशंका के मद्देनजर उसकी आसपास के क्षेत्रों में काफी समय तक खोजबीन किया गया। लंबे समय के बाद अत्यंत कमजोर स्थिति में जंगल के बीचों-बीच हाथी को पाया गया, हाथी के दोनों दांत काट लिये गये थे, जिसके चलते हाथी बेहद दर्द की स्थिति में था। इस बीच, घटना के संबंध में वन विभाग के लोगों को जानकारी देकर हाथी का इलाज शुरू किया गया है। दुष्कर्मी ने निर्दयता से जीवित हाथी के दोनों दांत काटने के कृत्य की सभी ने निंदा की है। प्रकृति प्रेमियों ने कहा है कि इसे मानवता का पतन कहा जा सकता है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि वन विभाग एवं पुलिस घटना को अंजाम देने वाले अवैध शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है।

रंगाली बिहू के पांचवें दिन मनाया जा रहा नांगल बिहू

गुवाहाटी (हिंस)। आज रंगाली बिहू के पांचवें दिन नांगल (हल) बिहू पूरे असम में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन बहाग महीने के पांचवें दिन के रूप में भी मनाया जाता है और *सात बिहू* के पांचवें दिन के तौर पर इसका विशेष महत्व है। यह पर्व मुख्य रूप से कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है और कृषक समुदाय द्वारा इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर किसानों ने आज सुबह अपने कृषि उपकरणों जैसे हल, जुआल और अन्य औजारों की साफ-सफाई कर उनके पास दीप और धूप जलाकर पूजा-अर्चना की। यह परंपरा आने वाले कृषि सत्र के लिए समृद्धि और अच्छी फसल की कामना का प्रतीक मानी जाती है। नांगल बिहू असम के कृषक जीवन में विशेष महत्व रखता है। बहाग बिहू के उल्लास के बाद यह दिन खेतों में उतरने की तैयारी का संकेत देता है। राज्यभर में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों ने पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा का पालन करते हुए अच्छी फसल और सुख-समृद्धि की कामना की।

अंकुर संघ का दो दिवसीय रंगाली बिहू कार्यक्रम का शुभारंभ

होजाई (निसं)। हमारी संस्कृति व परंपरा हमें बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है उक्त बातें आज होजाई के अंकुर संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय रंगाली बिहू के कार्यक्रम के दौरान नई पीढ़ी द्वारा अपने बुजुर्गों के सम्मान समारोह में अंकुर संघ के सचिव अनूप कुमार बरठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हम सबों का यह कर्तव्य है कि नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों का सम्मान एवं हमारी संस्कृति से अवगत करवाना। इसे नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति सम्मान देने की भावना बनी रहेगी। इसी कड़ी में आज पदमा बरठाकुर, सुरेंद्रनाथ डेका, जगदीश प्रसाद सुरेका, परमोदेश्वर बरकटकी, चंपा बरकटकी, गुरु प्रसाद बरठाकुर, हिंमत दास, कुशेश्वर मुदई,डॉ समसुल हक, लावण्या बोरा, दयाल चंद्र क्रो का सम्मान करते हुए फूलाम गमछा एवं मानपत्र भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया गया। उस वक्त का दृश्य देखते ही बनता था। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों ने युवाक-युवतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ अंकुर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विपुल चंद्र शर्मा ने संघ का ध्वज, विशिष्ट समाजसेवी व मोजेदार रंजन कुमार बोरा ने बिहू का ध्वज फहराया। इसके बाद समाज की महिलाओं द्वारा श्रीमयईअसमी गीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं, अंकुर संघ के सलाहकार व विशिष्ट समाजसेवी डॉ समसुल हक ने भारत रत्न डॉ भूपेन हजारीका की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया व विशिष्ट समाजसेवी सुरेंद्रनाथ डेका ने असम की धड़कन सुप्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के प्रतिछवि के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उपस्थित सभी संघ के कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दोनों महान विभूतियों को नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम में दसवीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों जिनमें कृषाक्षी कलिता, अभिज्ञान बरुवा, दर्शित शर्मा, दिव्यंका शर्मा, दर्पद कुमार शर्मा, रोनांगना रनक बरकटकी के साथ-साथ वर्ष 2025 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन व जर्नलिज्म विभाग में गोल्ड मेडल प्रथम स्थान के साथ सफलता अर्जित करने वाले नीलम कश्यप बरठाकुर का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी रंजन कुमार बोरा ने उपस्थित सभी जनों को विहूकी हार्दिक शुभकामनाएं दी। और कहा कि बिहू है तो असम है, असम है तो बिहू है। उन्होंने आगे कहा बिहू से ही हमारी पहचान है इसलिए हम सबको सद्भावना व हर्षोल्लास के साथ इसका आयोजन करना चाहिए। उक्त कार्यक्रमों के बाद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है, महान गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम को लघु रूप में आयोजित किया गया।

पूर्व शिक्षा मंत्री जतिन माली के निधन पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जताया शोक

गुवाहाटी (हिंस)। असम आंदोलन के नेता, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, पलासबारी क्षेत्र के चार बार के पूर्व विधायक जतिन माली का 69 वर्ष की आयु में गुवाहाटी के डाउनटाउन अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया। अपने घर पर उच्च रक्तचाप से प्रभावित होने के बाद परिवार के लोगों ने उन्हें डाउनटाउन अस्पताल में भर्ती कराया था। असम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और दरंग-उदालगुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिलीप सैकिया ने जतिन माली के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। शोक संतप्त परिवारजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के साथ-साथ दिवंगत आत्मा की चिर शांति की कामना करते हुए कहा कि माली के निधन से राज्य के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। पार्टी मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन से प्रेषित गए एक बयान में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मानस शरणिया ने यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि, असम आंदोलन के अग्रणी नेता जतिन माली 1985 में असम गण परिषद (अगप) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पलाशबारी क्षेत्र से पहली बार

विधानसभा चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर विजयी हुए थे। इसके बाद, उन्होंने 1991 और 1996 में लगातार तीन बार उसी क्षेत्र से विधायक के रूप में चयनित होकर अगप सरकार के समयकाल में दो बार शिक्षा मंत्री का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया। हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में उन्होंने पलाशबाड़ी क्षेत्र से नए संयुक्त मंच के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रतिद्वंद्विता पेश की थी। ऑल असम छात्र संघ (आसू) के पूर्व राज्य कार्यकारिणी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ वह दक्षिण कामरूप छात्र संघ के सलाहकार के रूप में भी जुड़े थे। असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दल के सदस्य के रूप में उन्होंने असम आंदोलन के दौरान एनएसए के तहत जेल का सामना किया। उन्होंने उत्तर-पूर्वी छात्रों के संघ के पूर्व अध्यक्ष, मिर्जा स्थित शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्थापक और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है।

ईवीएम और स्ट्रांग रूम का बहाना बनाकर पलायन का रास्ता तैयार कर रहे हैं गौरव गोगोई : मार्घेरिटा

जोरहाट (हिंस)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्घेरिटा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ईवीएम और स्ट्रांग रूम को मुद्दा बनाकर चुनाव परिणाम से पहले ही *पलायन का रास्ता* तैयार कर रहे हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई और असम कांग्रेस के नेता देवब्रत सैकिया- दोनों इस बार चुनाव में हार का सामना करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जोरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत निश्चित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जनता का व्यापक समर्थन एनडीए के पक्ष में है, जिसके चलते सभी सीटों पर जीत तय मानी जा रही है।

सेना के सीएसडी शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़

तेजपुर (हिंस)। असम के मिसामारी रेलवे स्टेशन के निकट सेना की कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के लिए निर्धारित शराब की एक बड़ी खेप की तस्करी के प्रयास का भंडाफोड़ किया गया है। संयुक्त अभियान के दौरान करीब 150 पेटी शराब जब्त की गई। यह खेप सेना के सीएसडी आउटलेटों के माध्यम से बिक्री के लिए निर्धारित थी, जिसे अवैध रूप से डिपो परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था। सटीक खुफिया सूचना के आधार पर असम पुलिस, तेजपुर स्थित सेना की गजराज इंटेलिजेंस यूनिट तथा स्थानीय सेना प्राधिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई प्रतिबंधित सीएसडी सामग्री को अवैध बाजार में पहुंचाने के एक सुनियोजित प्रयास का खुलासा करती है। समय रहते की गई इस कार्रवाई से अवैध वितरण को रोका जा सका और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी सामने आया।

भारतीय सेना ने गुवाहाटी आईआईटी परिसर में किया संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय सेना की रेड हॉर्न्स डिवीजन, गजराज कोर के तत्वावधान में शनिवार को आईआईटी गुवाहाटी में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास *एक्सरसाइज जल राहत* का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और आपदा से निपटने की तैयारी का प्रदर्शन किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में सेना के बाढ़ राहत दलों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान बाढ़ राहत अभियानों की कार्यप्रणाली, विभिन्न एजेंसियों की भूमिका तथा उन्नत तकनीक और नवाचारों के उपयोग को प्रदर्शित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य भीषण बाढ़ की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत बनाना था। इसमें वास्तविक

परिस्थितियों का अनुकरण करते हुए बचाव अभियान, ड्रोन के माध्यम से निगरानी, फंसे हुए ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाना और डूबते व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीमों ने गहरे पानी में बचाव अभियान का भी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना, राज्य प्रशासन, एसएसबी, सीएपीएफ और आपदा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लगभग 800 लोगों ने देखा, जिनमें एनसीसी और एनएसएस कैडेट तथा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र शामिल थे। गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नीरज शुक्ला ने बाढ़ राहत दलों की तैयारी का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने संबोधन में आपदा प्रबंधन में *समाज की समग्र भागीदारी* पर जोर देते हुए *प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोटेक्ट एवं प्रोवाइड* के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। इस अभ्यास से आम लोगों में सेना और अन्य एजेंसियों के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई। साथ ही भाग लेने वाली एजेंसियों ने भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण, मानक संचालन प्रक्रियाओं के अद्यतन और क्षमता निर्माण को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया।

10वीं की परीक्षा में 591 अंकों के साथ ज्योतिर्मय दास ने मारी बाजी

ज्योतिर्मय दास ने असम बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में 600 में से 591 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया, उनका लक्ष्य डॉक्टर बनना है। असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (एएसएसईबी) ने एचएसएलसी 2026 परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है, जिसमें ज्योतिर्मय दास ने 600 में से 591 अंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। शंकरदेव शिशु निकेतन, पाचरकुची में पढ़ने वाले ज्योतिर्मय की यह उपलब्धि उनकी असाधारण शैक्षणिक योग्यता और इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करती है। बजली जिले में मोरका गाँव के रहने वाले ज्योतिर्मय एक साधारण परिवार से हैं। परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य उनके पिता हैं, जो एक छोटे निजी हॉस्पिटल के अकाउंट विभाग में काम करते हैं। उनके परिवार की वार्षिक आय लगभग 1,20,000 रुपए है, जिसके कारण उनके परिवार को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी स्कूल की फीस और बुनियादी जरूरतें भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। इसके बाद भी उनके परिवार ने उनकी शिक्षा रुकने नहीं दी और अपने छोटे से घर के एक हिस्से को उनकी पढ़ाई का स्थान बना दिया। अपने पिता की मेहनत और स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए उन्हें जो संघर्ष करना पड़ता है, वह देखकर ज्योतिर्मय को डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली, ताकि वो उन लोगों तक इलाज पहुंचा सकें, जो इलाज का खर्च उठाने में समर्थ नहीं।

संपादकीय

परिसीमन पर सवाल-संदेह

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई.कुरैशी की चेतावनी है कि यदि परिसीमन के भरोसे रहे, तो 2034 के आम चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। यदि महिलाओं को राजनीति और नीति-निर्धारण में भागीदारी देनी है, तो 50 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर उतनी ही सीटें आवंटित की जा सकती हैं। मसलन-भाजपा-एनडीए को चुनाव में जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उसके मुताबिक लोकसभा में उनकी कुल 292 सीटें हैं। उसमें 50 फीसदी, यानी 146, सीटें जोड़ कर उन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह विपक्ष की 233 सीटों में 116 सीटें और जोड़ी जा सकती हैं। चूंकि संशोधन बिल के मुताबिक, लोकसभा में 543 से बढ़ कर 815 सीटें हो जाएंगी और 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी सदन में 273 महिलाएं सांसद बनकर आ सकेंगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का आकलन है कि जो जनगणना शुरू हुई है, वह 2027 तक जारी रहेगी। उसके नतीजे आने और संकलित होने में इतना वक्त खर्च होना मुमकिन है कि 2029 के आम चुनाव करीब खड़े दिखाई देंगे। यदि 2011 की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय किया गया है या किया जाना है, तो वह बुनियादी तौर पर विसंगत होगा, समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि देश की मौजूदा आबादी 147.66 करोड़ से अधिक है। क्या दोनों जनगणनाओं में अंतर नहीं है? क्या पुरानी जनसंख्या के आधार पर मौजूद आबादी के विकास, विस्तार, भौगोलिक बदलावों का परिसीमन किया जा सकता है? परिसीमन सरकार की मनमर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए। बेशक परिसीमन आयोग सर्वोच्च अदालत के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होता है और उसके निष्कर्षों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी आयोग की रपट पर पहले संसद की स्वीकृति अनिवार्य है और फिर राष्ट्रपति की मुहर अंतिम निर्णय है। देश के जम्मू-कश्मीर और असम के कुछ मामले, परिसीमन के बाद, सामने आए हैं, जो इतने असंतुलित और असमान हैं कि परिसीमन की ईमानदारी पर ढेरों सवाल और संदेह किए जा सकते हैं। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर जो संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया था, उस पर मत-विभाजन हो चुका होगा अथवा विपक्ष ने सामूहिक बहिर्गमन का रास्ता चुना होगा! इसका विश्लेषण बाद में करेंगे, क्योंकि यह घटनाक्रम शुक्रवार शाम तक होना था। बहरहाल इस संविधान संशोधन से पहले ही, गुरुवार देर रात्रि, 2023 में पारित किए गए कानून की सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके क्या 'तकनीकी कारण' हो सकते हैं? यह लोकतंत्र और संसद का अपमान है, क्योंकि महिला आरक्षण पर संसद में बहस जारी थी। अभी तक की चर्चा में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सीपीएम आदि विपक्षी दलों ने सतही तौर पर महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन परिसीमन के जरिए संघीयवाद, लोकतंत्र के उल्लंघन पर सवाल और संदेह जरूर किए। हम आज तक समझ नहीं पाए हैं कि विपक्ष दिन में कितनी बार 'लोकतंत्र की हत्या' मान लेता है और फिर उसी लोकतंत्र की आड़ में छिप कर राजनीति भी करने लगता है? बहरहाल लोकतंत्र कभी नहीं मरता, लेकिन जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो विसंगतियां हमें खोखला कर रही हैं, ये जरूर बदलनी चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 74-75 महिला सांसद हैं। उनका प्रतिनिधित्व 13.6 फीसदी बनता है। राज्यसभा में भी यह औसत करीब 17 फीसदी है और महिला सांसद 41 हैं। यदि महिला आरक्षण कानून, अंततः, लागू होता है, तो राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों की संख्या 4123 से बढ़ कर 6186 हो जाएगी। पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक, स्थानीय नगर निकायों में हजारों महिलाएं सक्रिय हैं। उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी हासिल हो रहा है। वे अब 'गूंगी गुड़िया' नहीं, मासूम नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक चेतना और जागृति से भरपूर हैं। देश की 'आधी जन-शक्ति' को संसद, विधानसभा के स्तर पर भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन मायनों में यह कानून वाकई एक क्रांतिकारी, ऐतिहासिक कदम, मील-पत्थर साबित हो सकता है। इस बदलाव को रोका नहीं जाना चाहिए।

> महिलाओं को राजनीति और नीति-निर्धारण में भागीदारी देनी है, तो 50 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर उतनी ही सीटें आवंटित की जा सकती हैं। मसलन-भाजपा-एनडीए को चुनाव में जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उसके मुताबिक लोकसभा में उनकी कुल 292 सीटें हैं। उसमें 50 फीसदी, यानी 146, सीटें जोड़ कर उन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह विपक्ष की 233 सीटों में 116 सीटें और जोड़ी जा सकती हैं। चूंकि संशोधन बिल के मुताबिक, लोकसभा में 543 से बढ़ कर 815 सीटें हो जाएंगी और 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी सदन में 273 महिलाएं सांसद बनकर आ सकेंगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का आकलन है कि जो जनगणना शुरू हुई है, वह 2027 तक जारी रहेगी। उसके नतीजे आने और संकलित होने में इतना वक्त खर्च होना मुमकिन है कि 2029 के आम चुनाव करीब खड़े दिखाई देंगे। यदि 2011 की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय किया गया है या किया जाना है, तो वह बुनियादी तौर पर विसंगत होगा, समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि देश की मौजूदा आबादी 147.66 करोड़ से अधिक है।

बाल विवाह पर रोक हो या महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में उठाए गए कदम

सामाजिक कल्याण बनाम धार्मिक हस्तक्षेप : संतुलन की अनिवार्यता

सौरभ वार्ष्णेय

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से एक टिप्पणी की सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। किसी भी अदालत के लिए लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल है। समाज के विकास और प्रगतिशीलता के नाम पर किए जाने वाले सुधारों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन जब यही सुधार किसी धर्म की मूल संरचना, परंपराओं और आस्थाओं को प्रभावित करने लगते हैं, तब एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है—क्या सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को कमजोर या खोखला किया जा सकता है? अगर हम इस टिप्पणी को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां अनेक धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां साथ-साथ विकसित हुई हैं, वहां यह सवाल और भी संवेदनशील हो जाता है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में सुधारों की प्रक्रिया को इस संवैधानिक संतुलन का सम्मान करना ही होगा। इतिहास गवाह है कि समाज में कई सुधार आवश्यक रहे हैं—चाहे वह सती प्रथा का उन्मूलन हो, बाल विवाह पर रोक हो या महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में उठाए गए कदम। इन सुधारों ने न केवल समाज को मानवीय बनाया, बल्कि धर्मों की आत्मा को भी शुद्ध किया। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि हर सुधार धार्मिक हस्तक्षेप है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुधार के नाम पर किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित किया जाता है, या उसकी आस्थाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। यह न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, बल्कि सुधारों के उद्देश्य को भी संदिग्ध बना देता है। सुधार यदि समानता, न्याय और मानवाधिकार के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हों, तो वे स्वीकार्य होते हैं; लेकिन यदि उनमें राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात झलकता है, तो वे विरोध को जन्म देते हैं। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे सुधार और आस्था के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। सुधारों का लक्ष्य कुरीतियों को समाप्त करना होना चाहिए, न कि किसी धर्म की पहचान को कमजोर करना। साथ ही, धार्मिक समुदायों को भी आत्ममंथन के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वे समय के साथ सकारात्मक बदलावों को स्वीकार कर सकें। यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण और धार्मिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं—बशर्ते दोनों के बीच संतुलन और संवेदनशीलता बनी रहे। सुधार तब ही सार्थक होंगे जब वे समाज को जोड़ने का काम करें, न कि उसे विभाजित करने का। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची जैसे न्यायमूर्ति अनुभवी हैं। इनकी अदालतों में कई ऐसे मामले आये होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान 9 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अनु'छेद 25(2)(ख) और अनु'छेद 26(ख) के तहत किसी धार्मिक संस्था को अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के बीच परस्पर संबंध पर दिए गए तर्कों को सुनते हुए यह टिप्पणी की। ज्ञात रहे कि अनु'छेद 25(2)(ख) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने या सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलने की अनुमति देता है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की ओर से पेश होते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि यद्यपि अनु'छेद 25(2)(ख) के तहत हिंदुओं के सभी संप्रदाय सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थान में प्रवेश की मांग कर सकते हैं, वहीं धार्मिक संप्रदाय को अनु'छेद 26(ख) के तहत आंतरिक अनुष्ठानों के संचालन को विनियमित करने का अधिकार होगा। उन्होंने अनु'छेद 25(2)(ख) और अनु'छेद 26(ख) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार का एक उदाहरण हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर आप धर्म को खोखला नहीं कर सकते।

आखिरकार सबरीमाला मामला क्या है ?

केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर चला विवाद केवल एक धार्मिक परंपरा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की एक जटिल परीक्षा बन चुका है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार, भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी आधार पर 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। समर्थकों का तर्क है कि यह परंपरा धार्मिक आस्था से जुड़ी है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, विरोधियों का कहना है कि यह प्रतिबंध महिलाओं के मौलिक अधिकारों—विशेषकर समानता और गरिमा—का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2018 में आया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए।

> समाज के विकास और प्रगतिशीलता के नाम पर किए जाने वाले सुधारों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन जब यही सुधार किसी धर्म की मूल संरचना, परंपराओं और आस्थाओं को प्रभावित करने लगते हैं, तब एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है—क्या सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को कमजोर या खोखला किया जा सकता है? अगर हम इस टिप्पणी को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां अनेक धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां साथ-साथ विकसित हुई हैं, वहां यह सवाल और भी संवेदनशील हो जाता है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में सुधारों की प्रक्रिया को इस संवैधानिक संतुलन का सम्मान करना ही होगा।

देश | दुनीया से

जमीनी लोकतंत्र का पुनर्सशक्तिकरण

भारत की आत्मा गांवों में बसती है', यह विचार केवल एक भावनात्मक कथन नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था का मूल दर्शन भी है। इसी दर्शन को साकार रूप देने के लिए पंचायती राज प्रणाली को विकसित किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया पुनः सक्रिय हो रही है, तब इस व्यवस्था की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का पुनः आयोजन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनस्थापना का महत्वपूर्ण आयाम है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के कारण स्थगित हुए ये चुनाव अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात सुनिश्चित हो पाए हैं, जो यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की निरंतरता कितनी अनिवार्य मानी जाती है। वर्ष 2021 की जनगणना कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, अतः वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जारी रोस्टर के तहत होने जा रहे ये चुनाव एक बार फिर ग्रामीण भारत की उस जीवंत परंपरा को सुदृढ़ करेंगे, जहां शासन की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। हिमाचल जैसे भौगोलिक रूप से जटिल राज्य में पंचायती राज संस्थाएं केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि विकास, सहभागिता और सामाजिक समरसता की धुरी हैं। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांवों में निहित हैं और पंचायती राज उसी जड़ प्रणाली को पोषित करने वाला तंत्र है, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति न होगी। पंचायती राज की अवधारणा कोई आधुनिक प्रयोग नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा का ही विकसित स्वरूप है, जहां 'पंच' निष्पक्ष न्याय और सामूहिक निर्णय का प्रतीक हुआ करते थे। आधुनिक भारत में इस व्यवस्था को वैचारिक दिशा महात्मा गांधी ने दी, जिन्होंने 'ग्राम स्वराज' के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वशासी गांवों का स्वप्न देखा। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक भारत के गांव सशक्त नहीं होंगे, तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। इसी सोच को संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करे। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में पंचायती राज संस्थाएं अपेक्षित सशक्तिकरण प्राप्त नहीं कर सकीं, लेकिन 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन ने इस दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नया भाग जोड़कर पंचायतों के गठन, अधिकार, संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसके साथ ही ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों को पंचायतों को सौंपा गया, जिससे उन्हें विकास कार्यों में वास्तविक भागीदारी मिली। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। पंचायती राज की तीन-स्तरीय संरचना जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद व्यवस्था ने ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। 1994 के पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में इन संस्थाओं को संगठित किया गया, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सुगमता से संभव हो सका। वर्तमान संदर्भ में, जब पंचायती राज चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जा रहे हैं, यह प्रश्न भी उठता है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में अद्यतन आंकड़ों का अभाव किस हद तक प्रतिनिधित्व की सटीकता को प्रभावित करता है। फिर भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखना सर्वोपरि है, और यही कारण है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही चुनाव कराए जा रहे हैं। यह स्थिति हमें यह भी स्मरण कराती है कि प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। वहीं ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक है, यह सत्य किसी पुष्टि का मोहताज नहीं। ये संस्थाएं न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम हैं, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की दिशा भी निर्धारित करती हैं। मनरेगा, स्वच्छता अभियान, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं का प्रभावी संचालन इन्हीं के माध्यम से संभव होता है। विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण ने ग्रामीण सत्ता संरचना में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है, जिससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बना है। इन वर्गों के लिए सीटों के आवंटन से एक तो अपने वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर उपयुक्त मंच पर बात रखने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर प्रभुत्वकारी व प्रभावशाली लोगों के चंगुल से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। नब्बे के दशक से पूर्व पंचायत प्रधान के सम्मान पट्ट ऐसे लोगों से भरे मिलेंगे, जिनका कार्यकाल पांच-पांच बार भी रहा है। लेकिन महिलाएं और वंचित वर्ग सदैव वंचित ही रहे या प्रतिनिधित्व रहा भी तो न के बराबर। यद्यपि आज सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका तो मिला है, फिर भी कुछ सवाल जरूर नजर आते हैं। क्या महिला व वंचित वर्गों में भी केवल उनको मौका मिल रहा है जो आर्थिक, या किसी अन्य आधार पर अपने वर्ग में सशक्त हैं? क्या प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व को केवल रबड़ स्टाम्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक सत्ता उनके शौहर के हाथ में होती है। कहीं-कहीं तो इसके साक्ष्य भी नजर आते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं केवल अपवाद मात्र ही हैं, जबकि अधिकतर साक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं व वंचित वर्गों के सशक्त नेतृत्व व सक्षम प्रतिनिधित्व के मिलते हैं। लोकतंत्र का आधार ही बहुमत है, अतः ऐसे अपवाद यदि हैं भी तो इन्हें जड़ मूल से निकाल फैंकने के लिए आज के शिक्षित समाज को आगे आना होगा। तभी सही मायनों में लोकतंत्र सफल होगा। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि पंचायती राज संस्थाओं को केवल औपचारिक ढांचे तक सीमित न रखा जाए।

> पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का पुन : आयोजन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनस्थापना का महत्वपूर्ण आयाम है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के कारण स्थगित हुए ये चुनाव अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात सुनिश्चित हो पाए हैं, जो यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की निरंतरता कितनी अनिवार्य मानी जाती है।

आप का | नजरीया

बगल में छुरी

शिक्षण परिसरों की निगरानी में कभी माहौल के आदर्श और केवल शिक्षा के लक्ष्य ही गूंजते थे, लेकिन अब यह दौर चुनौतियों से भरा है। सोलन के निजी विश्वविद्यालयों की छतें इतनी कमजोर कैसे हो गईं कि छात्र समुदाय अपनी हिम्मत हारने लगे हैं। मौत की छलांग का नजारा रौंगटे खड़े कर देता है, लेकिन घातक परिस्थितियों तक छात्र क्यों पहुंच रहे हैं, इस पर गौर करना होगा। एक दूसरा परिदृश्य सरकारी कालेजों के शरारती दरवाजे कर रहे हैं। अपनी कक्षाओं में ही तीन सहायक प्रोफेसर अपना आचरण नहीं बचा पाए। प्राध्यापकों के बगल में छुरी, आंखों में व्यभिचार और संगत में सारे दोष अगर होंगे, तो उनकी बर्खास्तगी का शुक्र मनाना चाहिए। वाकई इन सहायक प्रोफेसरों से कालेज की दीवारें कांपी होंगी, जब वे अपनी ही शिष्याओं के बीच दुष्चरित्र साबित हुए। अफसोस यह कि हिमाचल में अब छात्राओं को उन्हीं के प्रोफेसरों से खतरा है। अच्छी बात यह है कि इन तीनों मामलों के विरुद्ध पीड़ित छात्राओं ने खुद ही मोर्चा खोला और परिणाम स्वरूप लंबी जांच के बाद प्रोफेसरों को चलता कर दिया गया। कार्रवाई से निकले सबक दूर तक जाएंगे, लेकिन यह चिंता का विषय है कि शिक्षकों के वेश में खोट निकल रहे हैं। विडंबना यह भी है कि शिक्षक अब एक पाठ्यक्रम और सरकारी नौकर है। पिछले कुछ वर्षों से यह भी देखा जा रहा है कि इस पवित्र पेशे के आदर्श या तो राजनीति में दफन हो चुके हैं या पोस्टिंग के पहरावे में कुछ खास पहचान के लोग चमक रहे हैं। एक समय था जब शिक्षकों के मार्फत कोई छात्र खिलाड़ी, कोई गायक, कोई कलाकार, तो कोई साहित्यकार बन जाता था। तब शिक्षक पाठ्यक्रम से कहीं ऊपर जिंदगी के गुरु होते थे। पढ़ाने का तरीका और सलीका उनके प्रति गुरुत्व का आकर्षण और आगे बढ़ने की महत्त्वाकांक्षा पैदा करता था। खैर ये तीन प्रोफेसरों के चरित्र की कहानी नहीं, बल्कि हिमाचल के चेहरे से हो रही छेड़खानी ही मानी जाएगी। हिमाचल में कुछ विकृत प्रवृत्तियां और निरंकुश अदाकार पैदा हो रहे हैं। इसे सोशल मीडिया की पैदावार कहें या समाज के प्रति लापरवाह होता व्यक्तिगत स्वार्थ मानें। महिलाओं का आगे बढ़ना, उनका स्वतंत्र व जागरूक होना प्रदेश की छवि को खास बनाता है, लेकिन स्वतंत्रता और उद्दंडता के बीच अंतर कम होने लगा है। घुमारवीं में दो महिलाओं द्वारा कंडक्टर के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, किस समाज की परिभाषा में पुरस्कृत होगा और हैरानी यह कि ऐसे मौकों से जनता की जिम्मेदारी गायब हो रही है। हिमाचल में व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी ही बढ़ रही है, तो हम राज्य के सामाजिक संगठन में कैसे किसी आचार संहिता का पालन करेंगे। सोशल मीडिया पर उभरती टिप्पणियों का संज्ञान लें तो फिसाद की जड़ हमारे बीच है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया की नई मजदूरी से घायल होने की पूरी संभावना है। नाहन से तथाकथित इन्फ्लुएंसर युवती की हालिया वीडियो ने जिस तरह देश की सेवा में लगे फौजियों के व्यक्तित्व व चरित्र पर प्रहार किया है, उससे बड़ा अपशगुन हम नहीं देख सकते। यह मशहूर होने की ऐसी तालिका है, जहां हिमाचल के कई बच्चे आजकल भ्रमित हैं। पोर्टलों में ऐसे संपादक दिखाई देते हैं, जो बमुश्किल स्कूल की पढ़ाई भी शायद पूरी कर सके हैं। इन्हें प्रोत्साहन देते राजनीतिक नेता शब्द और सत्य की गुंजाइश में सिर्फ अपना गुणगान देख रहे हैं, तो प्रदेश की जानकारियों का जब-जब लबादा उतरेगा, सोशल मीडिया के गिरोह अपना काम कर चुके होंगे। बहरहाल शिक्षा विभाग ने तीन सहायक प्रोफेसरों को घर बिठा कर, एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आईंदा परिसरों का मिजाज दुरुस्त रहेगा। पढ़ाई या अध्ययन की परिपाटी में शिक्षकों की पहचान बदल रही है, क्योंकि शिक्षा के फार्मूलों में हम केवल डिग्रियों के अनुपात में व्यक्तित्व को तोलने लगे हैं।

> सोलन के निजी विश्वविद्यालयों की छतें इतनी कमजोर कैसे हो गईं कि छात्र समुदाय अपनी हिम्मत हारने लगे हैं। मौत की छलांग का नजारा रौंगटे खड़े कर देता है, लेकिन घातक परिस्थितियों तक छात्र क्यों पहुंच रहे हैं, इस पर गौर करना होगा। एक दूसरा परिदृश्य सरकारी कालेजों के शरारती दरवाजे कर रहे हैं। अपनी कक्षाओं में ही तीन सहायक प्रोफेसर अपना आचरण नहीं बचा पाए। प्राध्यापकों के बगल में छुरी, आंखों में व्यभिचार और संगत में सारे दोष अगर होंगे, तो उनकी बर्खास्तगी का शुक्र मनाना चाहिए। वाकई इन सहायक प्रोफेसरों से कालेज की दीवारें कांपी होंगी, जब वे अपनी ही शिष्याओं के बीच दुष्चरित्र साबित हुए। अफसोस यह कि हिमाचल में अब छात्राओं को उन्हीं के प्रोफेसरों से खतरा है। अच्छी बात यह है कि इन तीनों मामलों के विरुद्ध पीड़ित छात्राओं ने खुद ही मोर्चा खोला और परिणाम स्वरूप लंबी जांच के बाद प्रोफेसरों को चलता कर दिया गया। कार्रवाई से निकले सबक दूर तक जाएंगे, लेकिन यह चिंता का विषय है कि शिक्षकों के वेश में खोट निकल रहे हैं। विडंबना यह भी है कि शिक्षक अब एक पाठ्यक्रम और सरकारी नौकर है। पिछले कुछ वर्षों से यह भी देखा जा रहा है कि इस पवित्र पेशे के आदर्श या तो राजनीति में दफन हो चुके हैं या पोस्टिंग के पहरावे में कुछ खास पहचान के लोग चमक रहे हैं।

कुछ | अलग

देश के लिए ही तो कर रहा हूं

देखो भाई, विरोधियों की इस बात में कोई दम नहीं है कि मैं देश के लिए कुछ नहीं कर रहा। पूरी दुनिया जानती है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, वह अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए ही कर रहा हूं। देश हित में मैं सुबह 5.00 बजे उठ जाता हूं और उठकर सबसे पहले फेसबुक खोलता हूं। अपने विरोधियों को लताड़ लगता हूं। विरोधियों के खिलाफ कहीं कोई वीडियो या रील चल रही हो तो उसे मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूं। बाकी लोग मेरे फेसबुक पर आकर उस पर कमेंट करते हैं। कुछ मेरे विरोधियों को गाली देते हैं और कुछ विरोधियों द्वारा उकसाए गए लोग मुझे भी गाली देते हैं। जो मुझे गाली देते हैं, मैं उन गालियों को डिलीट कर देता हूं और गाली देने वालों को ब्लॉक कर देता हूं। यह सब कुछ मैं देश हित मे करता हूं ताकि देश में आपसी भाईचारा बना रहे। मैं विरोधियों के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचता हूं तो वह भी देश हित में रचता हूं क्योंकि विरोधी देश के लिए खतरा होते हैं। विरोधी अगर महंगाई को लेकर सरकार को पूछते हैं तो मैं उन विरोधियों की कोठियों की फोटो खींचकर अपने फेसबुक पर डाल देता हूं ताकि दुनिया को पता चले कि महंगाई की वजह से इन विरोधियों की संपत्ति कितनी बढ़ गई है और महंगाई होना देश हित में होता है। और हां, मैं केवल फेसबुक तक सीमित नहीं हूं, देशहित में मेरा विस्तार ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी तक भी है, क्योंकि आज के युग में देशभक्ति का असली मैदान यही है। सुबह की चाय के साथ मैं चार-पांच फॉरवर्ड तैयार करता हूं, जिनमें से कुछ आधे सच होते हैं और कुछ पूरे भावनात्मक, ताकि जनता का मनोबल बना रहे।

दृष्टि | कोण

कचरा प्रबंधन की लापरवाहियां

विश्व की पर्यावरणीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कचरे के कारण बड़ी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। न केवल मनुष्य समाज बल्कि समस्त जीव जगत और वनस्पतियां भी कचरा जनित प्रदूषण का दंश झेलने को अभिशप्त हैं। हवा, पानी और जमीन सब इस प्रदूषण की चपेट में है, जिससे वनस्पति और सारा जीव-जगत बीमारियों और जीवन संकट से गुजर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में विश्व की 18 फीसदी जनसंख्या निवास करती है और वैश्विक नागरिक अपशिष्ट में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसदी है। भारत प्रति वर्ष 620 लाख टन कचरा पैदा करता है जिसमें से केवल 430 लाख टन ही एकत्रित होता है, और 120 लाख टन ही उपचारित होता है। 310 लाख टन लैंड फिल में डाल दिया जाता है। शेष यहां-वहां पड़ा रहता है और जंगलों, ढलानों, खेतों, जल संसाधनों को प्रदूषित करता रहता है। उसमें से कुछ खुले में जलाया जाता है जो विषैली गैसों को स्थानीय स्तर पर फैला कर गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि सरकार की ओर से इस दिशा में प्रबंधन के लिए नियम समय-समय पर बनाए जाते रहे हैं, किन्तु खराब क्रियान्वयन के चलते स्थिति में कोई सुधार आता दिखाई नहीं देता है। गरीब बस्तियों के नजदीक डंपिंग, प्रबन्धन और लापरवाहियों से संबंधी डेटा के अभाव के चलते नीति निर्माण और क्रियान्वयन में बाधा होती है। उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए कि ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2026 सख्ती से लागू किए जाएं और लापरवाही करने वालों को दंडित करने के भी प्रावधान किए गए। मुख्य निर्देश निम्न हैं : ठोस कचरा 4 भागों में अलग करके इकट्ठा किया जाए : 1.गीला कचरा, जिसमें रसोई अपशिष्ट, भोजन, फल, सब्जियां आदि शामिल हैं, 2. सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच शामिल हैं, 3. सैनिटरी : नैपकिन, डायपर आदि के अलग अलग निपटारे की व्यवस्था करनी होगी, 4. विशेष श्रेणी में बल्ब, बैटरी, दवाइयां आदि के लिए विशेष अधिकृत इकाइयों को ही संशोधित करने के लिए देना होगा। गीले कचरे से मीथेन बना कर ईंधन के लिए प्रयोग करना। खासकर 100 किलो दैनिक सूखा अपशिष्ट, 40000 लीटर दैनिक पानी उपयोग करने वाली और 20000 वर्ग मीटर में फैली इकाइयां थोक अपशिष्ट उत्पादक घोषित की गई हैं जिन्हें गीला कचरा अपने परिसर में ही प्रसंस्कृत करना पड़ेगा। सूखा कचरा रिकवरी फैसिलिटी को पुनः चक्रीकरण के लिए देना होगा। सूखे कचरे में से जिसका पुनःचक्रीकरण संभव नहीं होगा, उसके पेलेट्स बना कर सीमेंट प्लांट और ऊर्जा उत्पादक इकाइयों को ईंधन के रूप में देना होगा, जिसकी मात्रा 5 फीसदी से बढ़ा कर 15 फीसदी की गई है। किसी भी तरह के पुनःचक्रीकरण या उपयोग के योग्य कचरे को ही लैंड फिल में डालने की अनुमति होगी। आम कचरा वहां डालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पुराने संचित अपशिष्ट को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यटक शुल्क लगा सकते हैं और पर्यटक संख्या नियंत्रित कर सकते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम बनाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निगरानी समितियों के माध्यम से नियम लागू किए जाएंगे। एक केंद्रीकृत पोर्टल कचरा उत्पादन, संग्रह और निपटारे की निगरानी करेगा और भौतिक सूचनाओं को डिजिटल ऑडिट में बदलेगा। प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से धन और ऊर्जा के रास्ते पर काम हो रहा है। प्लास्टिक कचरे का अलग से प्रसंस्करण करना, और प्रोजेक्ट री प्लान के तहत कैरी बैग निर्माण में 20 फीसदी कपास के रेशे मिलाने की योजना है।

मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला, गहलोत ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

जयपुर (हिंस)। दिल्ली में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 के पारित न होने की गूंज अब राजस्थान की राजनीति में तेज सुनाई देने लगी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद में हुए टकराव के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं और प्रदेश में इसे लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में जो हुआ, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके पर निशाना साधते हुए इसे *नारी शक्ति के अधिकारों पर प्रहार* बताया और कहा कि देश की महिलाएं आने वाले चुनावों में इसका जवाब देंगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से पता था कि विपक्ष के सहयोग के बिना बिल पास नहीं होगा, फिर भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। गहलोत ने कहा कि यह विधेयक परिसीमन के मुद्दे से जुड़ा था, जिससे विपक्ष को निशाना बनाने की आशंका थी। वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यह करोड़ों महिलाओं के सपनों पर आघात है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम था, जिसे विपक्ष ने रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के इस ऐतिहासिक अवसर को विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से खो दिया और देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेंगी। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विधेयक में कई खामियां बताते हुए इसे पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं बताया।

सपनों को नई उड़ान : मिस डेजर्ट राजस्थान में वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान

जयपुर (हिंस)। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाली युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस डेजर्ट राजस्थान के आयोजकों ने वाइल्डकार्ड एंट्री की घोषणा की है। इसके तहत वे प्रतिभागी, जो किसी कारणवश पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाईं, अब सीधे इस मंच तक पहुंचने का अवसर पा सकेंगी। आयोजक अरुण कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार गंगवाल और अमित कुमार खंडेलवाल के अनुसार यह पहल खास तौर पर उन टैलेंटेड युवतियों के लिए की गई है, जो फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन समय या अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर सकीं। वाइल्डकार्ड एंट्री के जरिए अब उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और सुनहरा मौका मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी वाइल्डकार्ड एंट्री के माध्यम से अब भी इस प्रतिष्ठित मंच का हिस्सा बन सकती हैं।

बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में तीन कट्टरपंथी गिरफ्तार

होशियारपुर (हिंस)। होशियारपुर के गांव नूरपुर जट्टा में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 30 और 31 मार्च 2026 रात को थाना माहिलपुर क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी संदीप मालिक के निर्देशों पर विशेष जांच टीमें गठित की गईं। पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेजऔर लगातार छापेमारी के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरकीरत सिंह (26) निवासी बड़ियां कलां, बननदीप सिंह (20) निवासी एसएएस नगर और साहिलप्रीत सिंह (22) निवासी एसएएस नगर के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी गुरकीरत सिंह वर्ष 2023 में अमेरिका गया था, जहां वह एक कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में आया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के बदले में करीब 50 हजार रुपए की राशि प्राप्त की और घटना का वीडियो बनाकर अपने हैंडलर को भेजा। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने समाज में नफरत और अशांति फैलाने की मंशा से यह वारदात की। घटना के दौरान उन्होंने एक ऑल्टो के-10 कार का इस्तेमाल किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा एक लोहे की रॉड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल घटना में किया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के संपर्क किन-किन लोगों से थे और उन्हें इस साजिश के लिए किस तरह से उकसाया गया। एसएसपी होशियारपुर संदीप मालिक ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

विश्व हेरिटेज दिवस के अवसर पर जयपुर मंडल का विरासत संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम

जयपुर (हिंस)। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा शनिवार को *विश्व हेरिटेज दिवस* के अवसर पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे की समृद्ध विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विरासत संरक्षण की शपथ दिलाकर की गई। अपने उद्बोधन में उन्होंने भारतीय रेल की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी है। उन्होंने आधुनिक तकनीक और परंपरागत मूल्यों के समन्वय पर बल देते हुए कहा कि हमें विकास के साथ-साथ अपनी ऐतिहासिक पहचान को भी संरक्षित रखना चाहिए। पूजा मित्तल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर ने बताया कि इस विशेष अवसर पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स में रेलवे के पुराने कलपुर्जों, ऐतिहासिक कोच डिजाइनों तथा पूर्व समय में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों की एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी ने उपस्थित जनों को भारतीय रेल के विकासक्रम की झलक प्रदान की और पुरानी तकनीकों की उपयोगिता को दर्शाया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा *हेरिटेज ड्राइंग प्रतियोगिता* का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से रेलवे की ऐतिहासिक धरोहरों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया। बच्चों के उत्साह और रचनात्मकता ने कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेलवे की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, पुरानी कार्यप्रणालियों के महत्व को रेखांकित करना तथा युवा रेलकर्मियों को संगठन की समृद्ध परंपराओं से जोड़ना रहा। इस पहल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विरासत का संरक्षण केवल जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि गौरव का विषय भी है। कार्यक्रम के समापन पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा सभी प्रतिभागियों की सराहना की गई। अंत में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (फ्रेट एवं ईएनएचएम) गौरव गुप्ता ने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को बधाई दी।

बजरंग दल का बड़ा प्रदर्शन, जिहादी मानसिकता एवं अवैध कब्जों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

जौनपुर (हिंस)। यूपी के जौनपुर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) बजरंग दल के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम 05 बजे एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन देश में बढ़ती *विकृत जिहादी मानसिकता*, अवैध कब्जों और सुनियोजित षड्यंत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर पॉलिटेक्निक चौराहा, कृषि भवन के निकट से शुरू हुआ। यह बाजिदपुर तिराहा और जेसीज चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट में एक सभा के रूप में समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौपा। बजरंग दल के जिला मिलन केंद्र प्रमुख आशुतोष सिंह ने इस अवसर पर कहा कि देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने वाली *जिहादी मानसिकता* अब राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और सद्भाव के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने इस मानसिकता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला संयोजक समर बहादुर सिंह ने कहा कि हाल ही में सामने आए कुछ प्रकरणों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नासिक में टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए मामले यह दर्शाते हैं कि *लव जिहाद* का जाल अब सुशिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। अमरावती में मोहम्मद अयाज नामक व्यक्ति द्वारा 180 नाबालिग हिंदू लड़कियों का कथित तौर पर शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला भी सामने आया है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि देशभर में जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कृत्य समाज में अशांति और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। संगठन ने देश के विभिन्न नगरों में वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, रेल विभाग और सेना की सुरक्षित भूमि पर सुनियोजित तरीके से किए जा रहे अवैध कब्जों पर भी चिंता व्यक्त की। बजरंग दल ने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बताया। ज्ञापन में यह कहा गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों और जनजाति समाज की अवयस्क बालिकाओं का शारीरिक व मानसिक शोषण कर उन्हें पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। बजरंग दल ने मांग की कि ऐसी राष्ट्र विरोधी और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध त्वरित एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठन ने *लव जिहाद* और जबरन धर्मांतरण जैसे कृत्यों को रोकने हेतु एक कठोर केंद्रीय कानून लागू करने की भी मांग की। बजरंग दल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रशासन से इन असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने का आग्रह किया, ताकि देश में शांति और सद्भाव बना रहे। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे, जिनमें उदयराज सिंह, लालमणि पांडेय, सूरज, अनिल कौशल, सत्येंद्र सिंह, सुनील मौर्य, महेंद्र सिंह, गणेश मोदनवाल, शिवम अग्रहरी, आनंद उपाध्याय, दीपक श्रीवास्तव, राहुल बाबा, कुबेर कुशवाहा, विशाल मोदनवाल, अवनीश मौर्य और शनि मौर्य समेत लोग मौजूद रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर विरोध में मतदान करने पर राजनीतिक माहौल गरमाया

सहरसा (हिंस)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने लोकसभा में बिल के विरोध में मतदान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। श्री साह ने कहा कि विपक्षी दल *पुरुषवादी सोच* से ग्रसित हैं और नहीं चाहते कि देश की महिलाओं को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण के पक्ष में रही है तथा पार्टी इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि देश की नारी शक्ति अब जागरूक हो चुकी है और विपक्ष के इस रुख को भलीभांति समझ रही है। भाजपा नेता ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 के पारित न हो पाने पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि यह केवल एक विधेयक का रुकना नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों, आकांक्षाओं और उनके सशक्त भविष्य के विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का यह ऐतिहासिक अवसर विपक्ष की वजह से अधूरा रह गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों का रवैया उनकी *संकीर्ण और महिला विरोधी मानसिकता* को दर्शाता है। श्री साह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को रोका गया है, लेकिन अब देश की महिलाएं सब देख और समझ रही हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नारी शक्ति का यह आक्रोश आने वाले समय में राजनीतिक रूप से असर दिखाएगा। श्री साह ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक बिल नहीं रोका, बल्कि करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को ठुकराया है। उन्होंने कहा कि आज जिन महिलाओं के सपनों को रोका गया है, वही नारी कल बदलाव की ताकत बनेगी और इतिहास लिखेगी। उन्होंने विपक्षी दलों से देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग भी की। आगे उन्होंने बताया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर 20 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान से एक विशाल आक्रोश मार्च निकालेगी, जिसमें लगभग 50 हजार महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस मार्च के माध्यम से महिला आरक्षण के समर्थन में जनजागरण किया जाएगा और विपक्ष के रुख के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहरसा जिले से भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस आक्रोश मार्च में शामिल होंगी। भाजपा नेता ने विश्वास जताया कि देश की नारी शक्ति आने वाले समय में अपने अधिकारों के प्रति और अधिक सजग होकर ऐसे निर्णयों का जवाब देगी तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भाजपा के प्रयासों को समर्थन देगी।

कैदी के हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज (हिंस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के महानिबंधक से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है कि कैसे और किन परिस्थितियों में जेल में बंद व्यक्ति ने शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल किया है और अधिवक्ता ने उसकी पहचान कैसे की है। कोर्ट ने पूछा है कि बिना शपथ कर्ता की मौजूदगी के शपथ आयुक्त ने उसके फोटो का सत्यापन कैसे कर लिया। या इसमें अन्य कोई तीसरा व्यक्ति भी लिप्त है। सभी बातों का रिपोर्ट में खुलासा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने सतीष कुमार उर्फ अमित की अर्जी पर दाखिल किया है। मामला है, 16 फरवरी 26 को एक हलफनामा दाखिल किया गया। जिस पर शपथ कर्ता श्याम सिंह के हस्ताक्षर हैं और सत्यापन शपथ आयुक्त ने किया है, जो 2 जनवरी 26 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि एक कैदी ने कैसे फोटो खिंचवाई और शपथ आयुक्त से सत्यापित हलफनामा कैसे दाखिल कर दिया। जमानत अर्जी की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की साजिश बेनकाब : सैलजा

सिरसा (हिंस)। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के नाम पर देश के लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे एकजुट विपक्ष ने समय रहते विफल कर दिया। सांसद ने शनिवार को जारी प्रेस बयान में कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का ऐसा जाल बुन रही थी, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगाड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। यह केवल महिलाओं के साथ छल नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि आज जो गिरा है, वह महिला आरक्षण विधेयक नहीं, बल्कि भाजपा की साजिशों का ढांचा है। यह देश की जागरूक जनता और मजबूत विपक्ष की जीत है, जिसने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। सांसद सैलजा ने मांग करते हुए कहा कि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अब किसी भी प्रकार की देरी या बहानेबाजी देश की महिलाओं के साथ अन्याय होगा, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बार-बार महिलाओं के सम्मान के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब देश की महिलाएं और युवा वर्ग भाजपा की नीयत को भलीभांति समझ चुके हैं। अंत में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। भाजपा चाहे जितनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है और आज से ही भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है।

निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में जनता की समस्याओं को उठाएगी कांग्रेस

चंडीगढ़ (हिंस)। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने चंडीगढ़ में आज बैठक का आयोजन करके घोषणा पत्र के मुद्दों पर चर्चा की। चुनाव घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में हुई इस बैइक में समिति के सदस्य विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक जसबीर मलौर, संजीव भारद्वाज, सतीश तेजली, तरुण चुघ तथा जयवीर आंतिल ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में आमजन को पेश आ रही समस्याओं तथा उनके व्यवहारिक एवं प्रभावी समाधान पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों ने जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों और अनुभवों को साझा करते हुए एक समावेशी घोषणा पत्र तैयार करने पर जोर दिया।

गैस की किल्लत से कोयला व लकड़ी की बढ़ रही मांग

नालंदा, बिहारशरीफ (हिंस)। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए 25 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस कारण जिस परिवार में अधिक संख्या है उनको अब खाना बनाने के लिए गैस के अलावा कोयला-लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन स्थल राजगीर में इन दीनों शादी विवाह को लेकर गैस मिलने के आसार कम होता देख लोग कोयला व लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। इसका सीधा असर स्थानीय बाजार और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। गैस की कमी के चलते अब लोग एक बार फिर कोयला और लकड़ी की ओर रुख करने लगे हैं। शादी-विवाह, तिलकोत्सव, जनेऊ और रिसेप्शन जैसे मांगलिक आयोजनों में पहले जहां रसोई गैस का व्यापक उपयोग होने लगा था, वहीं अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। गैस की अनुपलब्धता के कारण आयोजक फिर से कोयले पर ही भोजन और नाश्ते की सामग्री तैयार करवा रहे हैं। इससे कोयले और लकड़ी की मांग में अचानक तेजी आ गई है। बाजार में कोयले की कीमत भी बढ़ गई है। मौजूदा समय में कोयला 800 रुपए प्रति मन(40 किलो) बिक रहा है, जबकि कुछ समय पहले इसकी कीमत 600 रुपए प्रति मन थी। इसी तरह लकड़ी की कीमत भी 350 रुपए प्रति मन (40 किलो) तक पहुंच गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मांग में कोई कमी नहीं आई है। स्थानीय कोयला दुकानदार निर्मल द्विवेदी के अनुसार लगन के इस मौसम में कोयला और लकड़ी की बिक्री लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि दुकानदारों को हर 10-15 दिन पर नया स्टॉक मंगवाना पड़ रहा है। राजगीर में कोयला की तीन दुकान हैं। एक शहर के गिरियक रोड चौराहा पर, तो दूसरा बस स्टैंड के समीप छबिलापुर रोड और तीसरा सीवरेज रोड में है। तीनों प्रमुख दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखी जाती है। उधर रसोई गैस उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की बुकिंग अब 25 दिनों के अंतराल पर ही पूरी हो पा रही है, जिससे घरेलू रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर गैस संकट ने राजगीर में एक बार फिर पुराने समय की याद ताजा कर दी है, जब कोयला और लकड़ी ही रसोई के मुख्य साधन हुआ करते थे।

भगवान परशुराम का किया अभिषेक, शोभायात्रा आज

जोधपुर (हिंस)। भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के दूसरे दिन आज भी शहर में कार्यक्रम जारी रहे। सर्व ब्राह्मण महासभा और महोत्सव समिति की ओर से कार्यक्रमों के तहत सेवा कार्य और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर इकाई के तत्वावधान में भोगीशैल पर्वतमाला स्थित सिवांची गेट स्वर्गाश्रम के आगे परशुराम महादेव मंदिर चल रहे तीन दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आज भगवान परशुराम के विग्रह का विशेष अभिषेक किया गया। इस दौरान इत्र, पंचामृत, शहद, केसर एवं 101 किलो दूध से अभिषेक किया गया। साथ ही 51 वेदपाठियों द्वारा वेदमंत्रों के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। महासभा के जिलाध्यक्ष डॉ. आनंदराज पुरोहित ने बताया कि 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह विशेष पूजा-अर्चना तथा सायं छह बजे सम्मान समारोह आयोजित होगा। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सोलहवां परशुराम पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा, वहीं दो विशिष्ट व्यक्तियों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीत पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, डॉ. नगेंद्र शर्मा तथा अधिवक्ता आनंद पुरोहित विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ब्राह्मण समाज की ओर से ही 19 अप्रैल को भगवान परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को परमाणु ऊर्जा आयोग से मिली मंजूरी

नई दिल्ली

भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में एक कार्यशाला में घोषणा की गई कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को परमाणु ऊर्जा आयोग ने मंजूरी दे दी है और इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया है। यह पहल शांति अधिनियम 2025 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशाल वित्तीय संसाधनों को जुटाना है। केंद्रीय

2047 तक 100 गीगावाट लक्ष्य के लिए 20 लाख करोड़ की जरूरत

विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में परमाणु ऊर्जा विभाग की सदस्य (वित्त) सीमा जैन ने बताया कि एफडीआई पहल की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने क्षेत्र में धन की निरंतर आवक सुनिश्चित करने के लिए एक नए वित्तपोषण माडल की आवश्यकता पर जोर दिया। जैन ने अनुमान लगाया कि यदि 22 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के मानक आधार को लिया जाए, तो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लीट मोड विस्तार या एक ही साइट पर कई रिएक्टरों की स्थापना से समग्र अनुमोदन चक्र और संयंत्र स्थापना में लगने वाले समय में कमी आएगी। हालांकि, एनटीपीसी के एक अधिकारी ने निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों की ओर से अपेक्षित उत्साह की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद भी निजी क्षेत्र से उतनी रुचि नहीं देखी जा रही है, जितनी की उम्मीद थी। केंद्र सरकार के हर राज्य में कम से कम एक परमाणु संयंत्र स्थल की पहचान करने के निर्देश का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल लगभग 14 राज्यों के साथ काम चल रहा है और स्वीकृति दर उतनी अधिक नहीं है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने परमाणु क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना समय-सीमा और टैरिफ में कटौती की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नए संयंत्रों के लिए

न्यूज ब्रीफ

बजाज की लोकप्रिय बाइक डोमिनार 400 नए अवतार में पेश

नई दिल्ली। अपनी लोकप्रिय टूरिंग मोटरसाइकिल डोमिनार 400 को बजाज आटो ने नए अवतार में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसमें तकनीकी बदलाव करते हुए इंजन क्षमता को नया रूप दिया है, जिससे न केवल कीमत कम हुई है बल्कि प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नई डोमिनार 400 की सबसे चर्चा में रहने वाली बात इसकी कीमत में आई गिरावट है। अब यह मोटरसाइकिल पहले की तुलना में करीब 37 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है। राजधानी दिल्ली में इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 2,03,214 रुपये तय की गई है। यह कीमत में कमी इंजन क्षमता में बदलाव के कारण हुए कर लाभ का सीधा फायदा ग्राहकों को पहुंचाती है। नए माडल में अब 349.13 घन सेंटीमीटर का इंजन दिया गया है, जो पुराने 373 घन सेंटीमीटर इंजन के मुकाबले थोड़ा छोटा है। दिलचस्प बात यह है कि इंजन का आकार घटने के बावजूद, इसकी शक्ति में मामूली वृद्धि हुई है और यह अब लगभग 40.4 अश्वशक्ति की ताकत उत्पन्न करता है। नई डोमिनार 400 के बाहरी स्वरूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसका मजबूत और आकर्षक डिजाइन पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। इसमें उन्नत प्रकाश व्यवस्था के साथ पूर्ण प्रकाश वाले आगे के दीपक, दो डिजिटल मीटर, फिसलन रोकने वाली क्लच प्रणाली और संतुलन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत फ्रंट सस्पेंशन जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यह मोटरसाइकिल काफी भरोसेमंद मानी जा रही है, जिसमें आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ दोहरी चैनल एबीएस प्रणाली दी गई है।

पंजाब को राहत, केंद्र ने गेहूं खरीद मानकों में दी ढील, बेमौसम बारिश से प्रभावित फसल के लिए केंद्र सरकार ने घटाए गुणवत्ता मानक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार पंजाब से 2026-27 विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में ढील दे दी है। बेमौसम बारिश से प्रभावित फसल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। यह कदम पंजाब और चंडीगढ़ में गेहूं उत्पादकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार और एफसीआई-पंजाब के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए गेहूं की खरीद के लिए समान दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। नए मापदंडों के तहत, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अब पंजाब में 70 प्रतिशत चमक खो चुके और 15 प्रतिशत तक सिकुड़े हुए दानों वाले गेहूं को भी स्वीकार करेगा। पहले सिकुड़े हुए दानों की स्वीकार्य सीमा 6 प्रतिशत थी।

सोने-चांदी आयात को हरी झंडी, डीजीएफटी ने 15 बैंकों को दी अनुमति

नई दिल्ली। देश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित 15 प्रमुख बैंकों को सोने और चांदी के आयात की अनुमति दे दी है। इस फैसले से सीमा शुल्क पर अटके बहुमूल्य धातुओं की खेप को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे बाजार में आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिकृत इन बैंकों की सूची अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक वैध रहेगी। इसके अतिरिक्त, यूनियन बैंक आफ इंडिया और एसबीईआर बैंक को इसी अवधि के दौरान केवल सोने का आयात करने की अनुमति मिली है। इस अधिसूचना का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, जिसके कारण लगभग 5 टन सोना और 8 टन चांदी सीमा शुल्क पर अटकी हुई थी। यह मंजूरी विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जब सोने की मांग चरम पर होती है। अब बैंक इन फंसी हुई खेपों को क्लियर कर सकेंगे, जिससे बाजार में आपूर्ति की कमी की चिंता समाप्त हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत ने 72 अरब डालर के सोने और 12.1 अरब डालर की चांदी का आयात किया था।

होम लोन के हिडन चार्जेस से रहें सतर्क, सिर्फ ईएमआई पर भरोसा पड़ सकता है भारी

प्रोसेसिंग फीस से लेकर प्रीपेमेंट चार्ज तक बढ़ा सकते हैं कुल लागत

नई दिल्ली

अपना घर खरीदना हर मध्यमवर्गीय परिवार का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए लिया गया होम लोन कई बार अनजाने में आर्थिक बोझ भी बन सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि होम लोन लेते समय केवल मासिक ईएमआई पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो कुल लागत को काफी बढ़ा देते हैं।

इसे समझने के लिए उदाहरण दिया जा सकता है, कि यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये का होम लोन 8.5 फीसद वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए लेता है, तो उसकी मासिक ईएमआई लगभग 43,000 से 44,000 रुपये के बीच होती है। आमतौर पर ग्राहक इसी आंकड़े को आधार बनाकर निर्णय लेते हैं, जबकि वास्तविक खर्च इससे कहीं अधिक हो सकता है। बैंक द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अतिरिक्त शुल्क इस लागत में इजाफा करते हैं। इन शुल्कों में सबसे प्रमुख है प्रोसेसिंग फीस, जो लोन स्वीकृति के समय एकमुश्त ली जाती है। यह आमतौर पर लोन राशि का एक निश्चित प्रतिशत होती है और इसमें आवेदन प्रक्रिया तथा दस्तावेज़ों की जांच का खर्च शामिल होता है। इसके अलावा, यदि उधारकर्ता समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो उसे लेट पेमेंट पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। गंभीर मामलों में डिफाल्ट चार्जेज़ भी लगाए जाते हैं, जिनमें रिकवरी और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े खर्च शामिल होते हैं।

यहीं नहीं, यदि कोई ग्राहक अपने लोन का समय से पहले पूरा या आंशिक भुगतान करना चाहता है, तो उसे प्रीपेमेंट चार्ज भी देना पड़ सकता है। यह शुल्क बैंक द्वारा संभावित ब्याज के नुकसान की भरपाई के लिए लिया जाता है, जिससे उधारकर्ता की बचत की योजना प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति में वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि घर खरीदना जीवन का एक बड़ा आर्थिक निर्णय है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। उनके

अनुसार, ग्राहकों को लोन लेने से पहले सभी शर्तों और शुल्कों की पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रत्याशित खर्च का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर अच्छा होता है, उनके पास बैंकों से बेहतर ब्याज दर और कम शुल्क पर बातचीत करने का अवसर होता है। इसलिए, अलग-अलग बैंकों के आफर्स, नियम और शर्तों की तुलना करना बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ईएमआई के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, लोन की कुल लागत को समझना और सभी संभावित शुल्कों को ध्यान में रखना ही समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है, बल्कि लंबे समय में हजारों रुपये की बचत भी संभव है।

उन्नत सुविधाओं से लैस गाड़ियों को बाजार में उतारने की तैयारी

नई दिल्ली। साल-2026 उन ग्राहकों के लिए खास साबित होने वाला है, जो नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। कई कंपनियां न केवल अपने मौजूदा माडलों को नया रूप देने जा रही हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक और उन्नत सुविधाओं से लैस नई गाड़ियों को भी बाजार में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। देश की दो प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपने लोकप्रिय माडलों के नए संस्करण और विद्युत चालित विकल्प पेश करने की तैयारी में हैं। महिंद्रा अपनी सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में शामिल स्कार्पियो-एन का नया रूप पेश करने जा रही है, जिसमें बाहरी डिजाइन में हल्के बदलाव जैसे नई शैली की जाली और आधुनिक हेडलैंप शामिल होंगे। पारंपरिक स्कार्पियो के माडल को भी नया रूप दिया जाएगा, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और प्रीमियम लुक मिलेगा। महिंद्रा इस साल अपने विद्युत चालित वाहन पोर्टफोलियो को भी मजबूत करेगी, जिसमें मौजूदा माडलों में नई क्षमता वाले बैटरी विकल्प जोड़े जाएंगे। साथ ही, लोकप्रिय आफ-रोड गाड़ी थार का नया संस्करण भी जल्द बाजार में दस्तक दे सकता है, जिसमें आगे का हिस्सा अधिक आकर्षक और दमदार बनाया जाएगा। टाटा मोटर्स भी इस दौड़ में पीछे नहीं है और कंपनी अपनी नई सिएरा को विद्युत रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह गाड़ी मध्यम आकार की श्रेणी में आएगी और आधुनिक डिजाइन के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम होगी।

भारतीय ग्राहकों को मिल सकता है और ज्यादा ताकतवर स्कूटर का विकल्प

नई दिल्ली

मुंबई में सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपने प्रीमियम श्रेणी के बड़े स्कूटर, बर्गमैन 400 को पेश कर यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों को ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त स्कूटर का विकल्प भी मिल सकता है।

हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके आधिकारिक लान्च की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे देश में प्रदर्शित करने से यह स्पष्ट हो गया है कि सुजुकी भारतीय बाजार की प्रतिक्रिया को समझना चाहती है। बर्गमैन 400 को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम मैक्सी शैली के टूरिंग स्कूटर के रूप में जाना जाता है।

यह पारंपरिक स्कूटरों की तुलना में काफी बड़ा, आकर्षक और सुविधाजनक है, जिसका डिजाइन रोजमर्रा के उपयोग के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 400 सीसी क्षमता वाला तरल शीतलन प्रणाली से लैस एकल सिलेंडर इंजन है, जो इसे सामान्य स्कूटरों से अलग बनाता है। यह इंजन लगभग 28.5 अश्वशक्ति की ताकत और 35 न्यूटन मीटर का बल उत्पन्न करता है, जिसे स्वचालित गियर प्रणाली के साथ जोड़ा गया है।

आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो, इसमें पूरी तरह से प्रकाश उत्सर्जक डायोड आधारित लाइटिंग प्रणाली, अर्ध-डिजिटल सूचना पटल, ट्रैक्शन नियंत्रण प्रणाली और दोहरे चैनल वाला एंटी-लाक ब्रेकिंग सिस्टम शामिल है, जो सुरक्षा और नियंत्रण दोनों को बेहतर बनाता है। इसमें सीट के नीचे लगभग 42 लीटर का बड़ा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है।

अगर इसे भारत में लान्च किया जाता है, तो इसकी कीमत सबसे अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि प्रीमियम फीचर्स और बड़े इंजन के चलते यह सामान्य स्कूटरों से काफी अधिक हो सकती है।

समुद्री खनिज अन्वेषण पर जोर, नई नीति और वित्तपोषण की सिफारिश

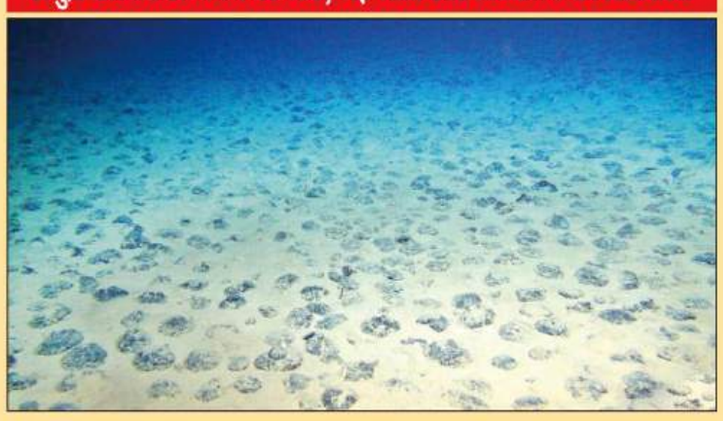

नई दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने भारत के समुद्री खनिज संसाधनों के दोहन की तैयारी में मौजूद कमियों को उजागर किया है। समिति ने एक समर्पित अपतटीय खनिज अन्वेषण नीति और विशेष फंडिंग व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है, खासकर तब जब सरकार के अपतटीय ब्लाकों की नीलामी के पहले प्रयास में निवेशकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। कोयला, खनन और इस्पात पर बनी इस संसदीय समिति ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट पर अपनी 23वीं रिपोर्ट में कहा है कि अपतटीय अन्वेषण, विशेषकर महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए, बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त समुद्री तल खनिजों का दोहन करने और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। समिति ने खान मंत्रालय से एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने की सिफारिश की है। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी एजेंसियों सहित अंतर-मंत्रालयी समन्वय और मजबूत फंडिंग की व्यवस्था को शामिल करने पर जोर दिया गया है। समिति का मानना है कि इन खामियों को दूर करके ही भारत अपनी समुद्री खनिज संपदा का प्रभावी ढंग से लाभ उठा पाएगा।

टीसीएस ने नासिक इकाई आरोपों पर जांच शुरू की, पीओएसएच शिकायतें नहीं मिलीं

डेलायट और ट्राइलीगल को स्वतंत्र वकील के तौर पर नियुक्त किया गया

नई दिल्ली

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपनी नासिक इकाई से संबंधित आरोपों पर गहन स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की है। एक बयान में कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसकी प्रारंभिक आंतरिक समीक्षा में नैतिकता या पीओएसएच (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) संबंधित चैनलों पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में कंपनी ने बोर्ड-स्तरीय निगरानी भी स्थापित की है ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

टीसीएस के सीईओ और एमडी के कृत्तिवासन ने कहा कि विस्तृत जांच अभी भी जारी है, लेकिन नासिक इकाई से संबंधित प्रणालियों और रिकार्डों की शुरुआती समीक्षा से पता चला है कि कंपनी को अपने पीओएसएच चैनलों पर उन विशिष्ट शिकायतों को प्राप्त नहीं हुआ है, जिनका कथित तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। इस जांच को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए, टीसीएस

ने डेलायट और ट्राइलीगल जैसे बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। ये विशेषज्ञ टीसीएस की एक मुख्य अधिकारी के नेतृत्व वाली आंतरिक जांच के लिए स्वतंत्र वकील के रूप में कार्य करेंगे।

कंपनी ने एक निगरानी समिति का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री करेंगे। जांच के निष्कर्षों को समीक्षा और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रक्रिया पर बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने नाशिक घटना से जुड़ी निदा खान (जिनका नाम इस मामले से जोड़ा जा रहा है) की भूमिका के बारे में भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थीं और उनकी भर्ती प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं थी। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया, उन्हें एक प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन पर कोई नेतृत्व संबंधित जिम्मेदारी नहीं थी। टीसीएस इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

महिंद्रा एंड मोहम्मद ने बंटवारे से पहले की थी महिंद्रा कंपनी की शुरुआत

नई दिल्ली

भारत के बंटवारे से पहले साल 1945 में पंजाब के लुधियाना में कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने दोस्त गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। इस साझेदारी में भरोसे और बराबरी को दिखाने के लिए कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया।

फिर आया साल 1947। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ न सिर्फ देश दो हिस्सों में बंटा,

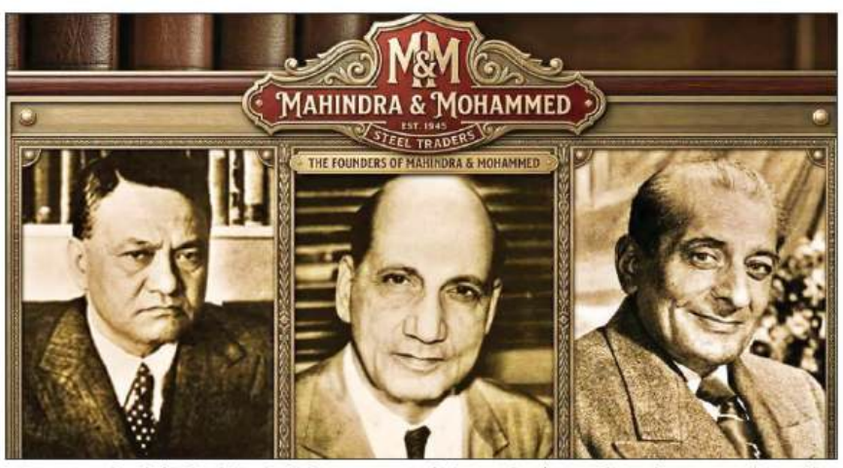

बल्कि इस साझेदारी में भी परिस्थितियों के कारण बदलाव आ गया। गुलाम मोहम्मद नए बने पाकिस्तान चले गए, जहां वे आगे चलकर देश के पहले वित्त मंत्री और बाद में गवर्नर-जनरल बने। वहीं, महिंद्रा भाइयों ने भारत में रहकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तब सबसे बड़ा सवाल था, कंपनी के नाम का क्या किया जाए एमएंडएम नाम कंपनी के दस्तावेज़ों और बिलों पर छप चुका था।

नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय, महिंद्रा भाइयों ने उसी पहचान को बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने नाम का फुल फार्म बदल दिया, लेकिन एमएंडएम को कायम रखा। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि बंटवारे के बाद भी रिश्ते खत्म नहीं हुए साल 1955 में जब गुलाम मोहम्मद भारत आए, तो उनका महिंद्रा परिवार से संपर्क बना रहा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की नींव सिर्फ 1945 में नहीं पड़ी थी, बल्कि इससे पहले ही इसकी बुनियाद तैयार हो चुकी थी। जगदीश चंद्र महिंद्रा और गुलाम मोहम्मद टाटा स्टील में साथ काम कर चुके थे, जिससे उनके बीच भरोसा विकसित हुआ। शुरुआत स्टील ट्रेडिंग से हुई, लेकिन जल्द ही कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम बढ़ाया। साल 1947 में ही कंपनी ने आटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री की और विलीज जीप्स को असेंबल करना शुरू किया।

1949 में, 75 विलीज जीप्स सीकेडी किट के रूप में भारत लाई गईं, जिन्हें मुंबई के मजगांव में असेंबल किया गया, और यही कदम कंपनी के आटोमोबाइल बिजनेस की मजबूत नींव बना। 1950 के दशक में कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही और 15 जून 1955 को महिंद्रा एंड महिंद्रा पब्लिक कंपनी बनी, जो 1956 में बाम्बे स्टाक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने ट्रैक्टर सेक्टर में कदम रखा, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ साझेदारी की। 1963 में केशुब महिंद्रा के चेयरमैन बनने के बाद कंपनी ने मित्सुबिशी और पेग्योट जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी कर और विस्तार किया। 1964 में, पोप पाल वीआई के भारत दौरे के दौरान एक खास महिंद्रा जीप का इस्तेमाल किया गया, जिसने कंपनी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।

आईपीएल 2026 में लगातार हार से निराश केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा- मुश्किल दिनों को अपनाना होगा

अहमदाबाद

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की खराब फार्म जारी है। टीम अपने शुरुआती छह मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। टीम को शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के 180 रन बनाने के बावजूद 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम की स्थिति पर खुलकर बात करते हुए खिलाड़ियों से सकारात्मक बने रहने और कठिन समय को स्वीकार करने की अपील की है।

मैच के बाद रहाणे ने कहा कि टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला इस सोच के साथ लिया था कि बल्लेबाज खुलकर खेल सकें।

उन्होंने कहा, हम बतौर बल्लेबाजी टीम इस विकेट पर 200 रन का लक्ष्य सोच रहे थे, जो चुनौतीपूर्ण होता।

हालांकि, उन्होंने कैमरन ग्रीन की पारी की जमकर तारीफ की। रहाणे ने कहा, कैमरन ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी की। आप विकेट गंवा सकते हैं, लेकिन हम 180 रन तक पहुंचे, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा।

लगातार हार के बावजूद रहाणे ने टीम को सकारात्मक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक खिलाड़ी के रूप में आपको कठिन दिनों को भी अपनाना पड़ता है। सिर ऊंचा रखें, हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरें और खुलकर खेलें।

गेंदबाजी को लेकर रहाणे ने साफ तौर पर माना कि पावरप्ले में टीम की कमजोरी सामने आई है। उन्होंने कहा, सच यह है कि पावरप्ले में गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी अनुभवहीन हैं। लेकिन वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही अभी सफलता नहीं मिल रही।

उन्होंने अनुकूल राय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों का समर्थन करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं। रहाणे ने यह भी बताया कि कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर सके क्योंकि उन्हें ऐंठन (क्रैम्प्स) की समस्या थी।

कप्तान ने अंत में कहा, जब आप लगातार हारते हैं तो नकारात्मक सोच आना आसान होता है, लेकिन मैं टीम पर गर्व करता हूं। हमें एक-एक मैच पर ध्यान देना है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है।

न्यूज ब्रीफ

फिंच ने आईपीएल में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सूची बनायी

सिडनी। पूर्व आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आरोन फिंच ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शेन वाटसन सहित पांच आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सूची बनायी है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में सबसे ऊपर उन्होंने आलराउंडर शेन वाटसन हैं, जिन्हें फिंच ने आईपीएल के इतिहास का सबसे महान आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा, उनका करियर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने राजस्थान से शुरुआत की और खिताब जीता। उन्होंने सीएसके में अपना करियर समाप्त किया और वहां भी खिताब जीता। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा और निरंतरता का प्रमाण है जिसने उन्हें आईपीएल के सबसे सफल आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक बनाया है। वाटसन ने अपनी आलराउंड क्षमता से कई बार अपनी टीमों को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है।आईपीएल का खिताब जीतने वाले कप्तान डेविड वार्नर को फिंच ने दूसरे नंबर पर चुना है। वार्नर इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान के तौर पर आईपीएल 2016 का खिताब जीता था। फिंच ने कहा, इस टूर्नामेंट में उन्होंने 66 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। इतने सालों में उनकी परफार्मेंस में जबरदस्त निरंतरता रही है। साथ ही वह एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सनराइजर्स के साथ मिलकर खिताब जीता है। इस सूची में तीसरे नंबर पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैं। फिंच ने आज के टी20 क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में उनकी लगातार अच्छी परफार्मेंस की प्रशंसा की। फिंच ने टिप्पणी की, इन सालों में इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हुए उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। दो अलग-अलग टीमों के साथ दो बार विजेता रहे हैं, इसलिए यह सिर्फ एक ही तरह की गेंदबाजी करने की बात नहीं है। उनके पास हर तरह की काबिलियत है। चौथे स्थान पर फिंच ने पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जानसन को चुना, और नई गेंद से उनके जबरदस्त प्रभाव को रेखांकित किया। फिंच के अनुसार, उनका असर जबरदस्त था, खासकर एकदम नई गेंद से। फिर से, इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस के साथ वह दो बार के विजेता रहे हैं।

टेबल टेनिस नेशनल : बंगाल की बेटियों ने रचा इतिहास, टाप सीड तमिलनाडु को 3-1 से हराकर जीता खिताब

देहरादून। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय हाल में खेली जा रही 87वीं यूटीटी अंतर-राज्यीय जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अंडर-19 गर्ल्स टीम फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त पश्चिम बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष वरीय तमिलनाडु को 3-1 से शिकस्त देकर खिताबी गौरव हासिल किया। खिताबी मुकाबले में बंगाल की अविषा कर्मकार ने पहले ही रबर में तमिलनाडु की पूर्व नेशनल चैंपियन एम. हंसिनी को 8-11, 11-6, 11-6, 11-7 से हराकर बंगाल को बढ़त दिलाई। हालांकि, तमिलनाडु की अनन्या मुरलीधरन ने सिंड्रेला दास को पांच गेम के कड़े संघर्ष में हराकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद डिट्सा राय ने श्रिया आनंद को 3-1 से हराकर बंगाल को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिलाई। अंत में सिंड्रेला दास ने एम. हंसिनी को सीधे गेमों में 11-3, 11-7, 11-8 से धूल चटाकर बंगाल की जीत पर मुहर लगा दी।

वीरेंदर सहवाग ने बताया, क्यों आरसीबी से की थी विराट कोहली ने शुरुआत, दिल्ली से क्यों चूके!

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की जब 2008 में शुरुआत हुई, तो फ्रेंचाइजियों ने आम तौर पर अपने गृह राज्य या शहर के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी थी। सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के लिए, राहुल द्रविड़ आरसीबी के लिए और वीरेंदर सहवाग दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेले। उस समय दिल्ली के विराट कोहली एक युवा और उभरते हुए स्टार थे। दिल्ली कैपिटल्स उन्हें अपनी टीम में तो जोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वीरेंदर सहवाग ने खुलासा किया है कि आखिर कोहली को दिल्ली से जोड़ने में पेच कहां फंसा और दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी जगह प्रदीप सांगवान पर दांव क्यों खेला। एक्सपर्ट सहवाग ने खुलासा किया कि दिल्ली कैपिटल्स का टाप आर्डर बैटिंग लाइन-अप पूरी तरह से भरा हुआ था। उनके पास कई बल्लेबाज थे, लेकिन गेंदबाजी में विकल्प कम पड़ रहे थे। सहवाग ने कहा, मुझे याद है कि 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की हमारी टीम में शिखर धवन भी थे और तिलकरत्ने दिलशान भी। उन्होंने आगे बताया, दोनों ओपनर थे लेकिन हम उन्हें नंबर 3 और नंबर 5 पर खेला रहे थे क्योंकि मैं और गौतम (गंभीर) पारी की शुरुआत करते थे। मनोज तिवारी चौथे नंबर पर उतरते थे।

टी20 विश्वकप की तैयारियों में लगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

नई दिल्ली

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 12 जून से 5 जुलाई इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले टी20 विश्वकप 2026 की तैयारी में लग गयी है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इसका खिताबी मुकाबला 5 जुलाई को ऐतिहासिक लार्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

इसी को देखते हुए भारतीय टीम अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी घरेलू श्रृंखला को टीम केवल एक सामान्य मुकाबला नहीं, बल्कि विश्व कप की तैयारी के एक अहम टूर्नामेंट के तौर पर देख रही है। यह श्रृंखला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर जब महिला टी20 विश्व कप नजदीक आ रहा है। टीम प्रबंधन इस मुकाबले में टीम संयोजन, खिलाड़ियों की मौजूदा फार्म और बेंच स्ट्रेंथ पर विशेष ध्यान देगा ताकि विश्व कप के लिए सर्वश्रेष्ठ एकादश तैयार की जा सके। कप्तान हरमनप्रीत ने टीम के आत्मविश्वास और मनोबल को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम हाल में मिली सफलताओं और अच्छे प्रदर्शन के बाद उत्साहित है और उनका लक्ष्य लगातार अच्छी क्रिकेट खेलना जारी रखना है। गौरतलब है कि टीम ने हाल के दिनों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है। हरमनप्रीत ने स्पष्ट किया कि यह श्रृंखला टीम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और खिलाड़ी इसे पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। उनका मानना है कि विश्व कप से पहले हर खिलाड़ी को पर्याप्त मौका देना आवश्यक है, ताकि अंतिम टीम संयोजन को पूरी तरह से आकार दिया जा सके। यह पांच मैचों की श्रृंखला टीम प्रबंधन को विभिन्न रणनीतियों और खिलाड़ी संयोजनों को आज़माने का अवसर प्रदान करेगी। कप्तान ने यह भी कहा कि खेल में हार-जीत तो चलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए सही दिशा में तैयारी करना और टीम में सही संतुलन स्थापित करना।

विश्वकप और एशियाई खेलों में अलग-अलग टीमें उतार सकता है हाकी इंडिया

नई दिल्ली। हाकी इंडिया, इस साल होने वाले दो बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों विश्व कप और एशियाई खेलों लिए अलग-अलग टीमें उतारने की योजना बना रहा है। यह कदम दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों के बीच बेहद कम समय अंतराल की चुनौती से निपटने के लिए उठाया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से एशियाई खेलों को अधिक प्राथमिकता मिलने वाली है।भारतीय टीम को बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाले पुरुष हाकी विश्व कप के समाप्त होने के ठीक बीस दिन बाद ही 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में एशियाई खेलों में भाग लेना है। इतने कम समय में खिलाड़ियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पुन: तैयार होना, अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म बनाए रखना, और चोटों से बचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यह मानते हुए कि भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ियों पर भारी बोझ पड़ेगा जिसको देखते हुए अलग-अलग टीमों को उतारने की रणनीति बनी है। इस रणनीति के पीछे मुख्य कारण एशियाई खेलों का 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन इवेंट भी है। जिसको लेकर हाकी इंडिया बेहद गंभीर है। उसका मानना है कि एशियाई खेल ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण जरिया है, इसलिए मुख्य और सबसे मजबूत टीम इसमें उतारी जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अपनी पूरी ताकत और अनुभव के साथ जापान में उतरेगा, जबकि विश्वकप के लिए एक युवा या मिश्रित टीम भेजी जा सकती है, जिसमें अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।पुरुष हाकी विश्व कप में भारतीय टीम को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 19 अगस्त को निर्धारित है, जिस पर दुनिया भर के हाकी प्रेमियों की निगाहें टिकी होंगी।

स्टटगार्ट ओपन: एंड्रीवा ने स्वियातेक को चौंकाया, सेमीफाइनल में रयबाकिना से भिड़ंत तय

स्टटगार्ट

स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां रूस की युवा खिलाड़ी मिर्रा एंड्रीवा ने दो बार की चैंपियन इगा स्वियातेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका सामना शीर्ष वरीय एलेना रयबाकिना से होगा।

18 वर्षीय एंड्रीवा ने शानदार वापसी करते हुए स्वियातेक को 3-6, 6-4, 6-3 से हराया। पहले सेट में पिछड़ने के बाद एंड्रीवा ने जबरदस्त खेल दिखाया और निर्णायक सेट में दो बार सर्विस ब्रेक कर मुकाबला अपने नाम किया।

इससे पहले, शीर्ष वरीय रयबाकिना ने कनाडा की लेयला फर्नांडीज को कड़े मुकाबले में 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (8/6) से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मैच करीब तीन घंटे तक चला, जिसमें रयबाकिना ने अंतिम सेट के टाईब्रेक में दो मैच प्वाइंट बचाकर शानदार जीत दर्ज की।

मैच के बाद रयबाकिना ने कहा, शुरुआत में काफी निराशा थी और मेरी सर्विस काम नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को संभाला और लय हासिल की।

स्वियातेक, जिन्होंने अपने छह ग्रैंड स्लैम खिताबों में से चार फ्रेंच ओपन की क्ले कोर्ट पर जीते हैं, इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही थीं, लेकिन एंड्रीवा के आक्रामक खेल के सामने टिक नहीं सकीं।

गौरतलब है कि एंड्रीवा ने पहले दौर में गत चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको को भी बाहर किया था, जिससे उनका आत्मविश्वास पहले ही बढ़ चुका था।

एंड्रीवा ने मैच के बाद कहा, मैं खुद से कह रही थी कि चाहे जो भी हो, मुझे लड़ते रहना है और विश्वास बनाए रखना है कि मैं किसी भी स्थिति से मैच जीत सकती हूं।

अब सेमीफाइनल में एंड्रीवा और रयबाकिना के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

कनमाडीकर ट्राफी : चंबल के रणबांकुरों के सिर सजा खिताबी ताज

इंदौर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) द्वारा आयोजित ए.डब्ल्यू. कनमाडीकर ट्राफी (बायज अंडर-13) के फाइनल मुकाबले में चंबल ने इंदौर के विरुद्ध शानदार खिताबी जीत दर्ज की। रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन मैदान पर खेले गए इस तीन दिवसीय फाइनल का परिणाम तकनीकी रूप से अनिर्णित (ड्रा) रहा, लेकिन पहली पारी में हासिल की गई 178 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त के आधार पर चंबल को विजेता घोषित किया गया। मैच के तीसरे और अंतिम दिन चंबल ने अपनी दूसरी पारी में 54/4 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर मौजूद आरव वशिष्ठ और माहिर खान ने इंदौर के गेंदबाजों की चुनौती का डटकर सामना किया। पहली पारी में शतक से चूके माहिर खान ने दूसरी पारी में भी 67 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, जबकि आरव वशिष्ठ ने 60 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों और कृष्णा तोमर (38 रन) व प्रभात तिवारी (24 रन) के उपयोगी योगदान की मदद से चंबल ने अपनी दूसरी पारी में 252 रन बनाए। पहली पारी की 178 रनों की बढ़त को मिलाकर इंदौर के सामने जीत के लिए 431 रनों का विशाल और लगभग असंभव लक्ष्य खड़ा हो गया। इंदौर की ओर से अथर्व जायसवाल ने 3 और प्रणय व प्रथम ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान इंदौर की टीम ने संभलकर शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज पवित्र पाटिल ने एक छोर संभाले रखा और 33 रन बनाकर नाबाद रहे। इंदौर ने दूसरी पारी में 55 ओवरों के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बनाए थे, तभी समय समाप्ति के कारण अंपायरों ने मैच ड्रा घोषित कर दिया। चूंकि चंबल ने पहली पारी में 178 रनों की निर्णायक बढ़त हासिल की थी, इसलिए नियमानुसार चंबल ट्राफी का हकदार बना।

प्रीमियर लीग में 25 साल बाद लौटा कोवेंट्री सिटी ब्लैकबर्न से ड्रा के साथ किया प्रमोशन पक्का

ब्लैकबर्न

कोवेंट्री सिटी ने 25 साल बाद प्रीमियर लीग में वापसी कर इतिहास रच दिया। टीम ने ब्लैकबर्न रोवर्स के खिलाफ शुक्रवार रात 1-1 से ड्रा खेलते हुए चैंपियनशिप से प्रमोशन सुनिश्चित कर लिया।

कोवेंट्री सिटी को प्रमोशन पक्का करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत थी, जिसे टीम ने हासिल कर लिया। मैच में ब्लैकबर्न ने दूसरे हाफ की शुरुआत में रयोया मोरिशिता के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन अंत में बाबी थामस ने हेडर से बराबरी का गोल कर टीम को जरूरी अंक दिला दिया।

इस ड्रा के साथ कोवेंट्री सिटी ने 43 मैचों में 86 अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत किया। तीसरे स्थान पर मौजूद मिलवाल उससे 13 अंक पीछे है और अब उसे पकड़ नहीं सकता।

टीम के कोच फ्रैंक लैम्पार्ड ने स्काई स्पोर्ट्स से इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह एक अविश्वसनीय पल है। हमें पता था कि हम करीब हैं, लेकिन 25 साल बाद इसे हासिल करना शानदार है। यह क्लब और इसके प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता है।

लैम्पार्ड के कोचिंग करियर में यह पहला प्रमोशन है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके करियर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है।

कोवेंट्री सिटी के लिए यह सफलता सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में पहुंचने पर क्लब को प्रसारण और अन्य स्रोतों से लगभग 120 से 170 मिलियन पाउंड तक की आय होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि कोवेंट्री सिटी ने 1967 में प्रमोशन के बाद लगातार 34 सीजन इंग्लैंड की शीर्ष लीग में बिताए थे, लेकिन 2000-01 सीजन में टीम को बाहर होना पड़ा। इसके बाद क्लब को आर्थिक और प्रदर्शन दोनों स्तरों पर कठिन दौर से गुजरना पड़ा।

2012 में टीम तीसरे डिवीजन में पहुंच गई और 2017 में चौथे डिवीजन तक गिर गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में टीम ने शानदार वापसी की और अब एक बार फिर इंग्लैंड के शीर्ष फुटबाल स्तर पर पहुंच गई है।

कोवेंट्री सिटी की यह वापसी क्लब और उसके प्रशंसकों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक पल साबित हुई है।

ऋषभ सहित शीर्ष क्रम के विफल होने से हार रही सुपर जाइंट्स : सिद्धू

नई दिल्ली

पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आईपीएल के इस सत्र में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खराब प्रदर्शन का कारण उसके कप्तान ऋषभ पंत का खराब प्रदर्शन है। सिद्धू ने कहा कि सुपर जाइंट्स की टीम ऋषभ के अलावा अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों एडेन मारक्रम, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श पर निर्भर है जिसमें से ऋषभ अब तक केवल एक ही मैच में रन बना पाये है। इससे पता चलता है कि लय में नहीं है पर इसका कारण गेंदबाज नहीं वह स्वयं हैं। सिद्धू ने कहा कि गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर रहे। वह स्वयं अपनी लापरवाही से विकेट गंवा रहे हैं। इससे उनकी टीम की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं।

इस विकेटकीपर बल्लेबाज का इस सत्र में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वह केवल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही नाबाद 68 रन की खेली खेल पाये हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली है। बेंगलुरु में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 5 विकेट की हार के दौरान भी वह केवल एक रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। वह लगातार रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पांच मैचों में केवल 104 रन बना पाए हैं, जिसमें उनका औसत 26.00 और स्ट्राइक रेट 122.35 का है, जो उनके क्षमता के अनुरूप बिल्कुल नहीं है।

सिद्धू ने कहा, उन्हें अपनी कमियों पर काफी गहराई से सोचने की जरूरत है। उनकी समस्याएं बनी हुई हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि उनका शीर्ष क्रम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वे अपने शुरुआती तीन बल्लेबाजों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मारक्रम, पूरन, मार्श और ऋषभ जैसे खिलाड़ियों में जबरदस्त क्षमता है पर उनके बीच साझेदारियों की कमी रही है। सिद्धू ने कहा, शीर्ष क्रम में 50 रन की साझेदारी भी बहुत कम देखने को मिली है।सिद्धू का मानना है कि गेंदबाज ऋषभ को आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह अपना विकेट स्वयं ही खो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, उनमें प्रतिभा और क्षमता दोनों हैं और अगर वह अपने को थोड़ा समय दें तो वह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। साथ ही कहा कि बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिलने से अभी टीम की गेंदबाजी पर भी दबाव है जिससे वह भी बिखर रही है।

आस्ट्रेलियाई टीम मई में एकदिवसीय सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी

कराची। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अगले माह मई के अंत में पाकिस्तान का दौरा करेगी। आस्ट्रेलियाई टीम इस दौरे में तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। ये मैच लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अनुसार इससे देश में क्रिकेट को एक नई उर्जा मिलेगी और बड़ी टीमें आने से नहीं हिचकेंगी। यह दौरा क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) और पीसीबी के बीच हुए एक करार का हिस्सा है। इस के तहत ही आस्ट्रेलियाई टी20 टीम ने पिछले साल टी20 विश्व कप से पहले पाक का ऐतिहासिक दौरा किया था और लाहौर में तीन टी20 मैच खेले थे। वह दौरा पाक में सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ था जिसके बाद अन्य टीम भी उसके यहां जाने लगीं थीं। इससे पाक में शीर्ष स्तर के क्रिकेट के आयोजन की उसकी क्षमता भी साबित हुई है। अब इसी भरोसे को देखते हुए कंगारु टीम एक बार फिर पाक के दौरे पर पहुंचेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मैच 30 मई से 5 जून के बीच आयोजित किए जाएंगे, जिसकी घोषणा जल्द ही क्रिकेट आस्ट्रेलिया और पीसीबी संयुक्त रूप से करेंगे।

... तो मुश्किल होगा नौकरी ढूंढना

धूम्रपान केवल सेहत को ही नहीं, बल्कि कामकाज और आमदनी को भी प्रभावित करता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की आमदनी धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति से काफी कम होती है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर और इस शोध के प्रमुख जूडिथ प्रोचास्का के अनुसार, धूम्रपान से सेहत को खतरा होता है ये बात तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन इस नए शोध में कहा गया है धूम्रपान से आमदनी पर भी असर पड़ता है। इस नए शोध में जूडिथ और उनके दल ने 131 ऐसे लोगों को शामिल किया जो बेरोजगार थे और धूम्रपान करते थे। इसके साथ ही इस शोध में 120 ऐसे बेरोजगार लोगों को भी शामिल किया गया जो धूम्रपान नहीं करते थे। धूम्रपान करने और न करने वाले प्रतिभागियों के बीच कई मामलों में अंतर पाया गया। उदाहरण के तौर पर धूम्रपान करने वाले प्रतिभागी आयु, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में धूम्रपान नहीं करने वाले प्रतिभागियों से पीछे थे। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि धूम्रपान नौकरी ढूंढने की क्षमता को प्रभावित करता है।

जौ-चने का सत्तू

चने को भूनने के बाद छिलका हटाकर पिसवा लेने पर चैथाई भाग जौ का सत्तू मिलाने से जौ-चने का सत्तू तैयार हो जाता है। इस सत्तू को पानी में घोलकर या घी-शक्कर मिलाकर पीने से गर्मी और बारिश के मौसम में खोई शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह ठक देने वाला होता है। चना गुणों में लघु, रुक्ष एवं शीतल होता है। रस में मधुर एवं कषाय होता है।

स्वस्थ बच्चों के लिए सावधानी जरूरी

हर मां-बाप यहीं चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहें लेकिन कई बार उन्हें सेहत संबंधी कई दिक्कतें आती हैं खांसी जुकाम के वह जल्द शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण उनकी या माता-पिता की गलत आदतें हो सकती हैं। उनकी जीवनशैली साफ-सुथरी होती है। यह माता-पिता की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह छोटी उम्र में ही बच्चों को स्वस्थ जीवन के लिए कुछ आदतें सिखाए ताकि वे स्वास्थ्य के प्रति जागरुक बन सकें। सावधानी बरतने पर हम बच्चों के बीमार होने की संभावनाएं कम कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो इन आदतों को अपने बच्चों को सिखाना न भूलें।

हाथ धोना सिखाएं: बच्चों को खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सिखाएं। हाथों में कई कीटाणु लगे होते हैं। उन्हें साफ रखने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

बच्चे को चुस्त रखें: व्यायाम करने से छोटी बीमारियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। एक तो व्यापाम से बच्चा चुस्त रहता है और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है।

भरपूर नींद: इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा समय पर सो जाए और अच्छी नींद ले सके। नींद की कमी से वह बीमार हो सकते हैं।

केयर: आंखें, नाक और मुंह कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां से कीटाणु आपके शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके बच्चे गंदे हाथों से अपने मुंह को न छुएं।

पौष्टिक आहार: अपने बच्चे को संतुलित आहार दें, जिसमें फल तथा हरी सब्जियां ज्यादा हो, जिससे रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

रूटीन चेकअप: कभी-कभी अपने बच्चे को फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएं और मामूली स्वास्थ्य मुद्दों की जांच के लिए रूटीन चैकअप करवाएं।

यह बात तो हर कोई जानता है कि धूम्रपान शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और इसके आदी लोगों को तो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा भी रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धूम्रपान करने से वजन बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। धूम्रपान अक्सर वजन घटाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन धूम्रपान वजन घटाने का बेहतर उपाय नहीं है। इसलिए वजन कम करने के लिए इसका कभी भी इस्तेमाल न करें। गर्भावस्था के दौरान मां धूम्रपान करती है तो बच्चे में अतिरिक्त चर्बी हो सकती है।

मेटाबोलिज्म रेट का बढ़ना

ज्यादा धूम्रपान करने से भूख नहीं लगती है और इस वजह से वजन घटता है। ऐसा धूम्रपान की वजह से निकोटीन खून के अंदर जाने से मेटाबोलिज्म रेट बढ़ जाने और भूख न लगने के कारण होता है।

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या

धूम्रपान करने वालों के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ जाती है। जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाती है।

अस्वस्थ शरीर

सामान्य लोगों की तुलना में धूम्रपान करने वाले लोग पतले होते हैं। धूम्रपान की वजह से वजन तो घटता ही है, लेकिन साथ ही शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए धूम्रपान करने से वजन नहीं घटता है बल्कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है।

स्मरण शक्ति पर असर

धूम्रपान करने से निकोटीन का असर दिमाग पर पड़ता है। धूम्रपान का दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि धूम्रपान करने वाले को लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है। जबकि वास्तव में धूम्रपान दिमाग से सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। धूम्रपान से स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है।

खाने का मन न करना

धूम्रपान से दिमाग के प्रभावित होने की वजह से आदमी अपनी नियमित दिनचर्या को भूल जाता है। खाने के समय थकान महसूस होती है जिसके कारण खाने का मन नहीं करता है। इसके कारण आदमी की दिनचर्या प्रभावित होती है जिसका असर पाचन क्रिया पर होता है। खाने में उचित अंतर न हो पाने की वजह से खाना अच्छे से नहीं पच पाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है।

कैलोरी का जलना

धूम्रपान करने के बाद आदमी के दिल की धड़कन बढ जाती है। सामान्य धड़कन की तुलना में आदमी का दिल 20 बार ज्यादा धड़कता है। जिसके कारण शरीर से कैलोरी बहुत तेजी से जलती है जिसकी वजह से शरीर का वजन घटता है। वजन घटना धूम्रपान करने वाले के सिगरेट पीने की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि आदमी अगर ज्यादा धूम्रपान करेगा तो कैलोरी ज्यादा जलेगी और वजन घटेगा। लेकिन गर्भावस्था में धूम्रपान करने वाली मां के बच्चों को किशोरावस्था में मोटापे की समस्या हो सकती है। मां द्वारा धूम्रपान करने से निकोटीन बच्चों में जमा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनमें 26 प्रतिशत ज्यादा चर्बी होती है। धूम्रपान करने से शरीर को बहुत नुकसान होते हैं। लेकिन धूम्रपान वजन बढने का कारण नहीं होता है। धूम्रपान से वजन घटता है। किंतु धूम्रपान को वजन घटाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि धूम्रपान से शरीर की मासपेशियां कमजोर होती हैं।

हेपेटाइटिस ठीक होती है इन घरेलू नुस्खो से

हेपेटाइटिस में व्यक्ति का लिवर (यकृत) ठोस हो जाता है जिससे पेट संबंधी कई परेशानियां होने लगती हैं। गंभीरता से न लेने पर यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके लिए कारगर उपायों के बारे में।

- गिलोय का 20 मिलिलीटर रस, आंवले व ग्वारपाठे का 10-10 मिलिलीटर रस मिलाकर दिन में दो बार लेने से पाचनक्रिया व पेशाब संबंधी रोगों में लाभ होता है।
- तुलसी की पत्तियों के एक चम्मच पेस्ट 200 मिलिलीटर मूली के पत्तों के रस में मिलाकर पीना भी इस रोग में लाभकारी है।
- मकोय के पत्ते, सफेद पुनर्नवा में हल्दी, काली मिर्च, धनिया व हल्का सेंधा नमक मिलाकर सब्जी बनाकर लेने से लिवर की कठोरता व सूजन में लाभ होगा।
- 15 मिलिलीटर ताजा गिलोय के रस में 20-25 किशमिश कूटकर मिलाएं। इससे उल्टी, पेट में जलन की समस्या में आराम मिलता है।
- मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते व पालक (तीनों 250 ग्राम मात्रा में) या दानामेथी के पत्तों के रस में 50 ग्राम चीनी व एक चम्मच नमक मिलाएं। इसे हेपेटाइटिस की पहली स्टेज व रोग ठीक होने के बाद दें। इससे खून की कमी दूर होती है।
- मूली के ताजे पत्ते खून व लिवर से अधिक बिलरुबीन (तरल जिसे लिवर बनाता है) निकालने में सक्षम होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर 15-20 मिलिलीटर रस दिन में दो बार लेने से पाचनक्रिया में सुधार होता है।
- कुटकी, चिरायता, सौंफ, इलाइची व सोंठ को एक चौथाई चम्मच सभी समान मात्रा में लेकर 2 चम्मच पानी मिलाएं व हल्का गुनगुना करें। इस पेस्ट को शहद में मिलाकर खाने से पाचनक्रिया दुरुस्त होगी।

टमाटर खाने से बीमारियों का खतरा होता है कम

टमाटर दुनियाभर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। हम हर रोज किसी न किसी रूप में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं फिर चाहे वे भोजन, सूप या सलाद ही क्यों न हो। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। टमाटर खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है तथा यह त्वचा संबंधित बीमारियों से भी राहत दिलाता है। टमाटर खाने से त्वचा जवां दिखती है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी यह रामवाण है। टमाटर में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इसमें दूध से दोगुनी मात्रा में आयरन पाया जाता है। यह सल्फर, कैल्शियम, और विटामिन्स की खान है और भूख बढ़ाने में सहायक है साथ ही कब्ज की समस्या को भी यह दूर करता है।

स्वस्थ त्वचा

टमाटर स्किन को सनबर्न से बचाता है और टैन्ड स्किन से भी राहत दिलाता है। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है।

पेट के लिए

पेट में कीड़े हों तो हर रोज खाली पेट टमाटर खाने से फायदा होता है। टमाटर में हींग का छौंका लगाकर पीजिए, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। टमाटर पर काली मिर्च लगाकर खाना भी काफी लाभदायक होता है।

भूख बढ़ाए

टमाटर भूख को बढ़ाकर पाचन शक्ति और पेट से संबंधित अनेक समस्याओं को दूर करता है। टमाटर खाने से पेट साफ रहता है और इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

डायबिटीज के लिए

टमाटर खाने से डायबिटीज रोगियों को बहुत फायदा होता है। हर रोज एक खीरा और एक टमाटर खाने से डायबिटीज रोगी को बहुत लाभ मिलता है। टमाटर पेशाब संबंधी रोगों के लिए भी फायदेमंद है।

मजबूत हड्डियां

टमाटर में विटामिन के और कैल्शियम दोनों ही पाए जाते है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और मरम्मत के लिए बहुत अच्छे होते हैं।

आंखों की रोशनी बढ़ाए

टमाटर में पाए जाने वाले विटामिन ए से आंखों की रोशनी तेज होती है और यह रतौंधी को रोकने में मदद करती है।

लीवर और किडनी

टमाटर लीवर और किडनी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हर रोज टमाटर का सूप पीने से लीवर और किडनी को फायदा होता है।

गठिया

अगर आपको गठिया है तो टमाटर का सेवन कीजिए। एक गिलास टमाटर के रस को सोंठ में डालकर अजवायन के साथ सुबह-शाम पीने से गठिया में फायदा होता है।

चुनौतियों और जोखिम से भरा काम

आपदा प्रबंधन में भी रोजगार के बेहतर अवसर

इन दिनों आपदा प्रबंधन में युवा कॅरियर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। चूंकि कुदरती आपदा अचानक आती है इसकी कोई तय सीमा नहीं होती। इसी के मद्देनजर 2005 में डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट बनाया गया। केंद्र और राज्य सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए हमारे देश में दो शाखाएं काम कर रही हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) और डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस (डीजीसीडी)। इनके जिम्मे डिजास्टर से संबंधित कई विभागों का काम होता है वहीं डीजीसीडी के अंतर्गत हर शहर और इलाके में टीमें होती हैं। ये छोटी शाखाओं में काम करते हैं।

संभावनाएं...

डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद ज्यादातर जॉब पब्लिक सैक्टर में हैं। जैसे सरकारी विभागों के फायर डिपार्टमेंट, सूखा प्रबंधन विभाग। विदेशों में छात्र अपना कॅरियर एमरजेंसी सर्विस, लोकल अथॉरिटी, राहत एजेंसी, एनजीओ, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रेड क्रॉस सोसायटी, यूनेस्को जैसी इंटरनैशनल एजेंसी में बना सकते हैं। इसमें पेशे में जनसेवा तो है जोखिम भी कम नहीं। इस जोखिम भरे काम के लिए वेतन भी बढ़िया मिलता है।

प्रमुख संस्थान...

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली
- दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
- इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेटी, मोहाली, पंजाब
- डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भोपाल, मध्यप्रदेश

योग्यता...

डिजास्टर मैनेजमैंट से संबंधित कई तरह के कोर्स मौजूद हैं। कोर्स के स्वरूप के अनुसार अंडरग्रैजुएट व सर्टिफिकेट कोर्स के लिए छात्र 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो। मास्टर तथा एमबीए सरीखे कोर्स के लिए स्नातक होना आवश्यक है। कुछ संस्थान पीएचडी भी कराते हैं। अतः उसके लिए मास्टर डिग्री जरूरी है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी एक विकल्प है। सिर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट जैस कई कोर्स हैं। रिस्क असेसमेंट एंड प्रीवेंशन स्ट्रेटेजीज, लैजिस्लेटिव स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन रेस्क्यू आदि विषय पढ़ाए जाते हैं।

विजय देवरकोंडा का नया अवतार, शौर्ययुव संग बड़े स्केल की फिल्म का एलान

अभिनेता विजय देवरकोंडा ने निर्देशक शौर्ययुव के साथ अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसने सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अनाउंसमेंट पोस्टर में विजय एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए हैं, जहां वह लोहे की जंजीरों से बंधे चार कुत्तों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म सिर्फ एक नई कहानी नहीं, बल्कि बड़े विजन और ग्लोबल स्तर के सिनेमाई अनुभव का हिस्सा बनने जा रही है। फिल्म के साथ *दैट्स ए रोर* नाम का एक थीम सॉन्ग भी जारी किया गया है। यह गीत संघर्ष, दर्द और मुश्किल हालात के बीच हार न मानने की भावना को दर्शाता है। गाने के बोल यह संदेश देते हैं कि असली ताकत शोहरत में नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने में है। मेकर्स का मानना है कि यह सिर्फ फिल्म का गाना नहीं, बल्कि उसके भावनात्मक मूल को दर्शाने वाला एक प्रतीक है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक समानांतर पौराणिक दुनिया पर आधारित होगी, जो प्राचीन एहसास के साथ पूरी तरह काल्पनिक होगी। निर्देशक शौर्ययुव, जिन्होंने *हाय नन्ना* से दर्शकों का दिल जीता था, अब एक बड़े स्तर की कहानी के साथ लौट रहे हैं। यह प्रोजेक्ट उनके अब तक के काम से काफी अलग माना जा रहा है और इसमें भावनात्मक गहराई के साथ भव्य विजुअल्स का संगम देखने को मिलेगा। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी टीम है। इसमें हॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के कई बड़े नाम जुड़े हैं, जिनमें सिनेमैटोग्राफर अलेजांद्रो मार्टिनेज, संगीतकार हेशम अब्दुल वहाब और अनुभवी वीएफएक्स विशेषज्ञ शामिल हैं। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक साहसी कदम साबित हो सकती है।

MEET OUR EXPERTS - APOLLO, CHENNAI
GASTRO SURGERY CLINIC
Apollo HOSPITALS CHENNAI
CONDITIONS / SYMPTOMS:
- Jaundice
- Ulcers
- Gallbladder stone
- Blood in motion
- Abdominal pain
- Acidity
- Piles & fistula
- Liver cirrhosis
- Alcoholic liver disease
- Fatty liver disease
- Hepatitis B & C
- Pancreas & bladde cancersr
- Esophageal cancers
- Gastroesophageal reflux disease
- Buming sensation in stomach
- Change in bowel habits
- Acute & chronic Pancreas disease
DR. M. PREETHI
MBBS, DNB (Med), MRCP, DM (Gastro)
Sr. Consultant Gastroenterologist
Apollo Hospitals, Chennai
25th April 2026
10:00 am - 4:00 pm
APOLLO HOSPITALS, CHENNAI
REGIONAL OFFICE - GUWAHATI
Rajgarh Main Road, Opp-Bylane - 10, Guwahati - 781003
For appointments 8404037649 / 0361-3102166

महिलाओं की उम्र बढ़ा सकती है 'कैमोमाइल'

वैसे तो दिन में एक कप चाय सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन नए शोधों में पता चला है कि कैमोमाइल (बबूने का फूल) की चाय महिलाओं की उम्र बढ़ा सकती है। कैमोमाइल एक प्राचीन पौधा है, जिसका कई औषधीय उपचारों में इस्तेमाल होता है। अध्ययन में पता चला है कि कैमोमाइल का सेवन महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

7 साल के अध्ययन के बाद सामने आया ये सच...

महिलाओं में यह जनसांख्यिकी कारकों से गुजरने, स्वास्थ्य परिस्थितियों एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के साथ सामंजस्य बैठाने में भी मददगार है, जबकि यह प्रभाव पुरुषों में नहीं देखा जाता है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मेडिकल शाखा के प्रोफेसर ब्रेट हॉवरी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच भिन्नता पाए जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन यह जरूर देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कैमोमाइल का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। शोधकर्ताओं ने अपने 7 साल के अध्ययन के दौरान मैक्सिकन-अमेरिकी लोगों में कैमोमाइल के प्रभाव और मृत्यु के कारणों का अध्ययन किया और पाया कि कैमोमाइल पीने वाले 1,677 महिलाएं एवं पुरुष 65 साल की आयु से ज्यादा जीवन जीते हैं।

पेट की गड़बड़ी-मोटापे की समस्या में मददगार...

शोधकर्ताओं ने हालांकि कहा कि यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि कैमोमाइल के सेवन और मृत्यु दर में गिरावट के बीच कैसा संबंध है। हाल के शोधों में पता चला है कि कैमोमाइल का सेवन हाइपरग्लिकेमिया, पेट की गड़बड़ी, मोटापे की समस्या और घबराहट की बीमारी के उपचार में मददगार है। कैमोमाइल को एक कारगर कॉलेस्ट्रॉल नियंत्रक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबॉयल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट भी माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कैमोमाइल महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**